Website : www.mantrabharat.com

जुनून है सच लिखने का

हिन्दी दैनिक

E-Mail : mantragwalior@gmail.com

संस्करण : ग्वालियर
वर्ष : 03
अंक : 138
पृष्ठ : 6
मूल्य : 2.00
गुरूवार,18 दिसम्बर 2025

मंत्र भारत

ग्वालियर, मुम्बई, लखनऊ एवं प्रयागराज,से एक साथ प्रकाशित एवं गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़ से प्रसारित

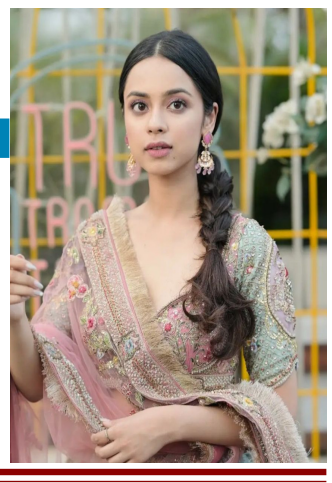

3 25 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन

4 मनरेगा से जी राम जी, भाजपा की सनक

5 मूवी डेट पर निकलीं 'लापता लेडीज' की फूल? जानिए किस एक्टर के

पीएसी स्थापना दिवसः सीएम योगी बोले

यूपी के आत्मविश्वास का कारण कानून का राज, प्रदेश की छवि बदली

सीएम योगी ने पीएसी के अदम्य साहस को भी गिनाया

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को पीएसी के स्थापना दिवस के अवसर पर पीएसी जवानों को संबोधित किया और बीते साढ़े आठ साल में पीएसी को और बेहतर बनाने के लिए किए गए कार्यों का जिक्र किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 78 वर्ष से पीएसी बल का इतिहास अनुशासन, शौर्य, त्याग व समर्पण का रहा है। उन्होंने जवानों से अपील की कि साहस, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा, व्यावसायिक दक्षता व कठिन प्रशिक्षण ही आपकी पहचान बननी चाहिए। सरकार आश्वस्त करती है कि आपके सम्मान व सरकार के स्तर पर मिलने वाली सुविधा-संसाधन में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। यूपी के अंदर आत्मविश्वास का प्रमुख कारण कानून का राज है। कानून का राज सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही सुशासन की गारंटी दे सकता है। सुशासन में ही निवेश सुरक्षित हो सकता है और सुरक्षित निवेश ही युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बन सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीपीएसी के स्थापना दिवस समारोह-2025 का शुभारंभ किया। सीएम ने पीएसी द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन व अवलोकन किया। सीएम ने 78वर्ष के गौरवशाली इतिहास के लिए पीएसी बल को बधाई दी। संवेदनशील परिस्थितियों में अग्रिम मोर्चे पर कार्य करता है पीएसी बल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में पीएसी बल आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, प्रदेश में महत्वपूर्ण त्योहारों, अतिविशिष्ट महानुभावों के आगमन, लोकतंत्र के महापर्व ह्यचुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सुनिश्चित करने के साथ ही संवेदनशील परिस्थितियों में अग्रिम मोर्चे पर कार्य करता है। पीएसी के अधिकारी व कार्मिक विभिन्न आयामों के माध्यम से न सिर्फ यूपी, बल्कि देश के अंदर यूपी पीएसी बल, एसएसएफ, यातायात पुलिस, प्रतिसार निरीक्षक ड्यूटी, प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षक, एटीएस व एसटीएफ कमांडो के रूप में सेवाएं प्रदान कर कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। सीएम योगी ने पीएसी के अदम्य साहस को भी गिनाया सीएम योगी ने पीएसी बल के अदम्य साहस की चर्चा की। बताया कि 30वीं वाहिनी पीएसी के जवानों ने 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले का जवाब दिया और पांचों आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। जुलाई 2005 में श्रीराम जन्मभूमि परिसर अयोध्या में आतंकी हमले के दौरान सीआरपीएफ, पीएसी और यूपी पुलिस की संयुक्त टीम ने सभी आर्तकियों को मार गिराया गया था। यूपी की बेहतर छवि को देश के सामने रखने मे मिली सफलता सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने पीएसी की 46 कंपनियों को पुनर्जीवित करते हुए यूपी के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखा और आंतरिक सुरक्षा के माध्यम से यूपी की बेहतर छवि को देश के सामने प्रस्तुत करने में सफलता हासिल की। संख्या, क्षमता, प्रशिक्षण, तकनीक के स्तर पर पीएसी की सशक्त बनाने का कार्य निरंतर जारी है। अत्याधुनिक हथियारों व दंगा नियंत्रण उपकरणों से सुसज्जित करते हुए पीएसी को एसएलआर, इंसास राइफल, मल्टीसेल लांचर, एंटी राइड गन, टियर गैस गन समेत अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण भी प्रदान किए गए।

यूपी की बेहतर छवि को देश के सामने रखने मे मिली सफलता

दिल्ली की हवा में जल्द सुधार की उम्मीद

मंत्री बोले, आगामी सप्ताह में AQI बेहतर होगा, 50% वर्क फ्रॉम होम लागू

नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने आगामी सप्ताह में वायु गुणवत्ता सूचकांक (अदक) में सुधार के लिए 50% कार्य-गृह व्यवस्था और पीयूसी प्रमाणपत्र अनिवार्य जैसे कड़े कदम उठाने की घोषणा की है, हालांकि प्रदूषण का स्तर अभी भी 'अत्यंत खराब' श्रेणी में है। निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों पर प्रतिबंध और बीएस6 वाहनों के उपयोग की अपील के बावजूद, विपक्ष सरकार पर प्रदूषण नियंत्रण में विफलता का आरोप लगा रहा है।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार प्रयासरत है और यह भी बताया कि अब 50% कार्य-गृह व्यवस्था लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक है। आने वाले कुछ दिनों में पिछले साल के आंकड़ों की तुलना में स्थिति में कोई खास सुधार की उम्मीद नहीं है, इसलिए हम स्थिति को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं... हम आने वाले सप्ताह में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। दिल्ली में 50% कार्य-गृह व्यवस्था लागू होगी, जो एक महत्वपूर्ण कदम है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कल से, मैं दिल्लीवासियों से अपील करता हूं कि वे अपना पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण) प्रमाणपत्र प्राप्त कर लें। पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना उन्हें ईंधन नहीं मिलेगा। दिल्ली में निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है... मैं दिल्ली के बाहर से आने वाले लोगों से अपील करता हूं कि वे भारत स्टेज 6 (बीएस6) उत्सर्जन मानकों का पालन करने वाले वाहन लाएं।

सार संक्षेप

घने कोहरे के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर100 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं

नई दिल्ली। भारत के उत्तरी भागों, जिनमें दिल्ली भी शामिल है जो एयर इंडिया का प्रमुख केंद्र है। इन स्थितियों का अक्सर एयरलाइन नेटवर्क के उड़ान समय पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यापक देरी और उड़ानें रद्द हो जाती हैं। दिल्ली हवाई अड्डे पर कम दृश्यता के कारण उड़ान संचालन बाधित हुआ, जिससे एयरलाइंस को बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के एक अधिकारी के अनुसार, घने कोहरे के कारण 131 उड़ानें रद्द की गईं। अधिकारी ने कहा कि कम दृश्यता के कारण दिल्ली हवाई अड्डे से अब तक 52 प्रस्थान और 79 आगमन रद्द किए जा चुके हैं। भारत के उत्तरी भागों, जिनमें दिल्ली भी शामिल है जो एयर इंडिया का प्रमुख केंद्र है। इन स्थितियों का अक्सर एयरलाइन नेटवर्क के उड़ान समय पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यापक देरी और उड़ानें रद्द हो जाती हैं।

अहमदाबाद के तीन स्कूलों को बम की धमकी मिली; पुलिस हाई अलर्ट पर

अहमदाबाद : पुलिस ने बताया कि जिन स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले, उनमें वेजलपुर-जीवराज पार्क में जाइडस स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जेबर स्कूल फॉर चिल्ड्रन, महाराजा अग्रसेन विद्यालय और डीएवी इंटरनेशनल स्कूल शामिल हैं। अहमदाबाद के तीन स्कूलों को आज ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के जॉइंट पुलिस कमिश्नर शरद सिंघल ने बताया कि पुलिस टीमें संबंधित स्कूलों में मौजूद हैं। बुधवार सुबह अहमदाबाद के कई स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिलने से दहशत फैल गई और छात्रों को बाहर निकाला गया, क्योंकि पुलिस, फायर सर्विस और बम निरोधक टीमों ने पूरे शहर में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। पुलिस ने बताया कि जिन स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले, उनमें वेजलपुर-जीवराज पार्क में जाइडस स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जेबर स्कूल फॉर चिल्ड्रन, महाराजा अग्रसेन विद्यालय और डीएवी इंटरनेशनल स्कूल शामिल हैं। इसके तुरंत बाद, निर्माण स्कूल, जेम्स जेनेसिस इंटरनेशनल स्कूल, डिवाइन चाइल्ड स्कूल और आविष्कार स्कूल से भी इसी तरह के ईमेल मिलने की सूचना मिली। अधिकारियों के अनुसार, पहली अलर्ट सुबह करीब 10 बजे मिली, जिसके बाद स्थानीय पुलिस टीमें स्कूलों में पहुंचीं।

प्रधानमंत्री मोदी ने इथियोपिया संसद में कहा

शांति, सुरक्षा और कनेक्टिविटी के मामले में मजबूत भागीदारी

अदीस अबाबा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत और इथियोपिया को प्राचीन ज्ञान और आधुनिक आकांक्षाओं का संगम बताते हुए कहा है कि दोनों देशों को विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक स्तर पर और बुलंद करने के लिए एकजुट होकर प्रयास करना होगा। श्री मोदी ने इथियोपिया की दो दिन की यात्रा के अंतिम दिन बुधवार को यहां इथियोपियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इथियोपिया की पहली द्विपक्षीय यात्रा पर गये श्री मोदी ने संसद को संबोधित करने के अवसर को गौरवपूर्ण बताते हुए कहा, लोकतंत्र के इस मंदिर के माध्यम से वह इथियोपिया के आम नागरिकों, किसानों, उद्यमियों, गौरवशाली महिलाओं और उन युवाओं से संवाद कर रहे हैं जो देश का भविष्य गढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उन्हें इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान 'ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया' प्रदान किए जाने के लिए इथियोपिया की जनता और सरकार का आभार व्यक्त किया। दोनों देशों के बीच संबंधों के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर गहरा संतोष व्यक्त किया कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्राचीन संबंधों को सामरिक साझेदारी का दर्जा दिया गया है। भारत और इथियोपिया के बीच सभ्यतागत संबंधों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश प्राचीन ज्ञान और आधुनिक आकांक्षाओं का संगम हैं। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि भारत का राष्ट्रीय गीत ₹वंदे मातरम्₹ और इथियोपिया का राष्ट्रगान, दोनों ही अपनी भूमि को मां के रूप में संबोधित करते हैं। दोनों देशों के साझा संघर्ष की ओर संकेत करते हुए प्रधानमंत्री ने 1941 में इथियोपिया की मुक्ति के लिए इथियोपियाई नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इथियोपियाई जनता के बलिदानों का प्रतीक अदवा विजय स्मारक को श्रद्धांजलि अर्पित करना उनके लिए सम्मान की बात है। प्रधानमंत्री ने भारत-इथियोपिया साझेदारी को और सशक्त तथा व्यापक बनाने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने इथियोपिया की वृद्धि और समृद्धि में भारतीय शिक्षकों और भारतीय व्यवसायों के योगदान का स्मरण किया। उन्होंने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण और नवाचार सहित भारत के विकास अनुभव साझा किए और इथियोपिया की प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास सहयोग जारी रखने की भारत की तत्परता व्यक्त की। ₹वसुधैव कुटुम्बकम₹ (विश्व एक परिवार है) के सिद्धांत में निहित मानवता की सेवा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान इथियोपिया को टीकों की आपूर्ति करना भारत के लिए गौरव की बात थी। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि 'वैश्विक दक्षिण' के देशों के रूप में भारत और इथियोपिया को विकासशील देशों की आवाज को और मजबूत करने के लिए एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। उन्होंने वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष को सुदृढ़ करने में इथियोपिया की एकजुटता के लिए आभार व्यक्त किया।

उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसफर किया रेप-हत्याकांड का मामला

कलकत्ता HC करेगा ट्रेनी डॉक्टर के केस की सुनवाई

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान से शुरू की गयी कार्यवाही को कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया, ताकि मामले में जारी निदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी की जा सके। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने निर्देश दिया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय अब इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन की निगरानी करेगा। पीठ ने कहा, हम इसे उचित समझते हैं कि मामले को कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ को भेजा जाए, और मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध है कि मामले को उपयुक्त पीठ के समक्ष रखा जाए। रजिस्ट्री को सभी रिकॉर्ड कलकत्ता उच्च न्यायालय को भेजने का निर्देश दिया जाता है। न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भी निर्देश दिया कि वह उच्चतम न्यायालय में जमा की गई स्थिति रिपोर्ट की प्रतियां पीड़िता के माता-पिता को उपलब्ध कराए। उच्चतम न्यायालय ने अगस्त 2024 में इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया था! उस घटना के बाद देशभर में डॉक्टरों और मेडिकल एसोसिएशनों द्वारा जवाबदेही और मेडिकल कार्यस्थलों पर बढ़ी हुई सुरक्षा की मांग को लेकर व्यापक प्रदर्शन शुरू कर दिए थे।

हिजाब वीडियो को लेकर उमर अब्दुल्ला ने नीतीश कुमार पर कसा तंज

अब असली चेहरा सामने आ रहा है

जम्मू । जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक वायरल वीडियो को लेकर तीखा प्रहार किया, जिसमें कथित तौर पर उन्हें एक महिला का हिजाब हटाने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री को धर्मनिरपेक्ष नेता माना जाता था, लेकिन अब उनका असली चेहरा सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इस तरह की हरकतें अस्वीकार्य हैं। उन्होंने अतीत में जम्मू और कश्मीर में हुए चुनावों के दौरान हुई इसी तरह की एक घटना का जिक्र किया। अब्दुल्ला ने पत्रकारों से कहा कि यहां भी, चुनावों के दौरान, महबूबा मुफ्ती ने मतदान केंद्र पर एक महिला मतदाता का बुर्का हटवाया था। वह

भी दुर्भाग्यपूर्ण था, और यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले नीतीश कुमार को धर्मनिरपेक्ष नेता माना जाता था। अब नीतीश कुमार का असली चेहरा सामने आ रहा है। पटना में एक सरकारी कार्यक्रम का वीडियो वायरल होने के बाद विपक्षी दलों की ओर से इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। इस वीडियो में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक महिला को प्रमाण पत्र देते समय उसका हिजाब खींचते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो ने देशभर में आक्रोश पैदा कर दिया है। वीडियो में यह घटना मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित एक समारोह के दौरान घटी, जहां नए भर्ती हुए आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे थे। महिला के कुछ कहने से पहले ही कुमार ने हाथ बढ़ाकर उसका हिजाब नीचे कर दिया, जिससे उसका मुंह और ठोड़ी दिख गई।

टोल नाकों पर कैमरों से सारा काम होने के कारण रोज होने वाले झगड़ों से मिलेगा छुटकारा : गडकरी

नई दिल्ली। टोल नाकों पर विवाद और मारपीट की घटनाएं होने की बात स्वीकार करते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि अब यहां कैमरे लगने के कारण कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, जिससे विवाद की आशंका समाप्त हो जाएगी। गडकरी ने राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा, ह्यह्यअभी कोई व्यक्ति नहीं खड़ा रहेगा टोल नाकों पर। कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, कोई झगड़ेगा नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। उन्होंने कहा कि वहां कैमरा काम करेगा और एक प्रकार से यह समस्या समाप्त हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने उनसे प्रश्न पूछा कि टोल नाकों पर होने वाली हिंसक

घटनाओं और झगड़ों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? इसके जवाब में गडकरी ने स्वीकार किया कि टोल नाकों पर पहलवान और विशेष तरह के लोग रहते थे। उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसे लोग, ह्यह्यगुंडागर्दी करते थे, जबरदस्ती करते थे, लाठियां मारते थे, अपमानजनक व्यवहार करते थे...यह सच है। अब इन सब की छुट्टी हो जाएगी। अब कोई दिखेगा नहीं, आप चिंता मत करिए। गडकरी ने टैग योजना के बारे में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि देश में करीब एक हजार टोल नाके हैं जहां पहले नकदी से लेनदेन होता था और फिर फास्ट टैग व्यवस्था शुरू की गयी। उन्होंने कहा कि अब मल्टी लेयर व्यवस्था की शुरूआत हो रही है। उन्होंने कहा कि इस नयी व्यवस्था के लिए दस अनुबंध दिये गये हैं और दस अभी प्रक्रियागत हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने तय किया है कि दिसंबर 2026 तक पूरे देश में यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि फास्ट टैग से संबंधित धोखाधड़ी के 6,725 मामले सामने आये हैं। उन्होंने कहा कि अभी सरकार ने एक वाहन, एक फास्ट टैग की नीति शुरू की है, फिर इसमें नंबर प्लेट को भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस नयी नीति के कारण किसी वाहन के लिए फास्ट टैग लेना और उससे कोई अन्य वाहन टोल से निकल जाने की घटनाएं बहुत ही कम हो गयी हैं।

राहुल-सोनिया को कोर्ट से राहत के बाद बोले खड़गें

पीएम मोदी, अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए

नई दिल्ली : बुधवार सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए खरगे ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले का उद्देश्य गांधी परिवार को परेशान करना है और यह राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से दायर किया गया है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार सुबह भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोपपत्र का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। आरोपपत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम शामिल किया गया है। बुधवार सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए खरगे ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले का उद्देश्य गांधी परिवार को परेशान करना है और यह राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से दायर किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अदालत का यह फैसला नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मुंह पर तमाचा है। उन्हें इस्तीफा देकर यह कहना चाहिए कि भविष्य में वे जनता को परेशान नहीं करेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले को ₹झूठा₹ बताते हुए खार्गे ने कहा कि इसे राजनीतिक प्रतिशोध और दुर्भावना की भावना से आगे बढ़ाया गया है। खरगे ने कहा कि इस अखबार की शुरूआत 1938 में स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी, जिसे भाजपा सरकार अब मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजों से जोड़कर बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि सच तो यह है कि इस मामले में कोई सच्चाई नहीं है।

'मैन्युफैक्चरिंग भारत में घट रही', मजबूत इकोसिस्टम बनाने की जरूरत : राहुल

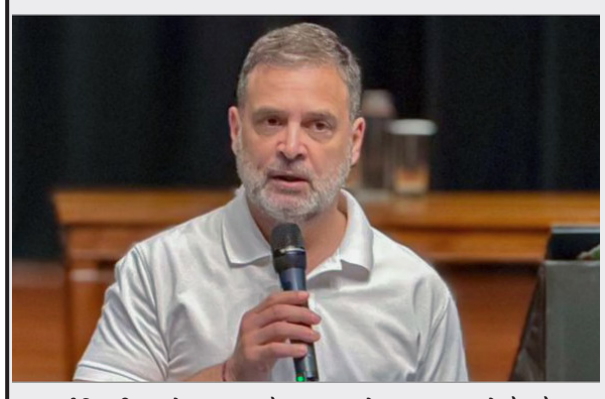

नई दिल्ली : कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जर्मनी के दौरे पर हैं, इस दौरान उन्होंने म्यूनिख में बीएमडब्ल्यू प्लांट का दौरा किया। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा- भारत में मैन्युफैक्चरिंग घट रही है, मजबूत इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है।

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि निर्माण मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ होती है, लेकिन दुर्भाग्य से भारत में यह लगातार कमजोर हो रही है। उन्होंने जोर दिया कि तेज आर्थिक विकास के लिए देश को सार्थक और मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार करने होंगे। राहुल गांधी ने यह बात जर्मनी की यात्रा के दौरान कही। म्यूनिख में बीएमडब्ल्यू वेल्ट और बीएमडब्ल्यू प्लांट म्यूनिख के गाइडेड टूर के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा किए। 'इटह की विश्वस्तरीय मैन्युफै क्चरिंग देखना शानदार अनुभव' उन्होंने कहा कि बीएमडब्ल्यू की विश्वस्तरीय मैन्युफैक्चरिंग को करीब से देखना एक शानदार अनुभव था। इस दौरे की खास बात टीवीएस मोटर कंपनी की 450सीसी मोटरसाइकिल को देखना रही, जिसे बीएमडब्ल्यू के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। राहुल गांधी ने इसे गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि जर्मनी में भारतीय इंजीनियरिंग को प्रदर्शित होते देखना खुशी की बात है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग घट रही है- राहुल गांधी उन्होंने कहा, 'मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की नींव मैन्युफैक्चरिंग पर टिकी होती है। लेकिन भारत में मैन्युफैक्चरिंग घट रही है। अगर हमें विकास की रफ्तार बढ़ानी है तो हमें ज्यादा उत्पादन करना होगा, मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने होंगे और बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण नौकरियां पैदा करनी होंगी।' बता दें कि राहुल गांधी जमर्नी की यात्रा पर प्रोग्रेसिव अलायंस के निमंत्रण पर गए हैं। इस दौरान वे भारतीय प्रवासी समुदाय से संवाद करेंगे और जर्मन सरकार के मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी के दौरे पर हैं, इस दौरान वे वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से और जर्मनी सरकार के मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे।

रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा दुल्लहपुर-मऊ रेल खण्ड के दोहरीकरण का संरक्षा निरीक्षण

गोरखपुरः पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल पर दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण परियोजनाओ के साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास का क्रम निरन्तर जारी है। इसी क्रम में, वाराणसी मंडल के भटनी-औंड़िहार रेलखण्ड पर दुल्लहपुर-मऊ (21 किमी) खण्ड का विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 17 दिसम्बर, 2025 को रेल संरक्षा आयुक्त, उत्तर पूर्व सर्किल श्री प्रणजीव सक्सेना ने संरक्षा निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण में उनके साथ पूर्वोत्तर रेलवे के प्रमुख मुख्य इंजीनियर श्री नीलमणि, मंडल रेल प्रबंधक, वाराणसी श्री आशीष जैन, कार्यकारी निदेशक(रेल विकास निगम लिमिटेड) श्री विकास चन्द्रा, मुख्य परियोजना प्रबंधक(रेल विकास निगम लिमिटेड) श्री आशुतोष शुक्ला सहित मुख्यालय, मंडल तथा रेल विकास निगम लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे । रेल संरक्षा आयुक्त, उत्तर पूर्व सर्किल श्री प्रणजीव सक्सेना ने अपने निरीक्षण का आरंभ दुल्लहपुर रेलवे स्टेशन पर विद्युतीकरण के अनुरूप इलेक्ट्रानिक इंटरलॉकिंग, संरक्षा गियरों के बदलाव, स्टेशन वर्किंग रुल, रिले रूम के एक्सटेंशन, यार्ड में पड़ने वाले समपारों के दोहरीकरण के अनुरुप विस्तार तथा स्टेशन पर दोहरीकरण के अनुरूप प्लेटफार्मों एवं पैदल उपरिगामी पुल के क्लियरेंस तथा मानक सूची और उपलब्धता के अनुसार यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया। इसके पश्चात वे मोटर ट्राली से दुल्लहपुर-पिपरीडीह रेल खण्ड का निरीक्षण करते हुए किमी 72/3 पर रेल ओवर ब्रिज में सेस्मिक अरेस्टर और बियरिंग के प्रावधान का निरीक्षण किया और उन्होंने खण्ड में पड़ने वाले फाउंडेशन, पाइप तथा कुशनिंग की जाँच करते हुए लॉन्ग वेल्ड रेल संख्या 2 के दोनों छोर पर स्विच एक्स्टेंशन जॉइंट और मध्य बिंदु पर रीडिंग के साथ मापन किया गया । तदुपरांत गति प्रतिबंध के साथ कर्व संख्या-01 के इन्डेन्ट का मापन करते हुए पिपरीडीह स्टेशन पहुंचे और दोहरीकरण सह विद्युतीकरण के अनुरूप स्टेशन के उपकरणों के बदलाव एवं यात्रियों की सुरक्षा के प्रबंध का निरीक्षण किया । इस दौरान उन्होंने स्टेशन के केंद्रीकृत वी डी यू पैनल, रिले रूम, पावर सप्लाई रूम आदि का निरीक्षण किया । इस दौरान उन्होंने पिपरीडीह यार्ड में फेसिंग पॉइंट सं- 101ए तथा पिपरीडीह स्टेशन तथा यार्ड में पड़ने वाले समपार संख्या 5/बी-2 का संरक्षा निरीक्षण कर संरक्षा परखी। इसके उपरान्त रेल संरक्षा आयुक्त मोटर ट्राली से पिपरीडीह-मऊ ब्लाक सेक्शन का निरीक्षण करते हुए मऊ पहुंचे इस दौरान उन्होंने इस रेल खण्ड पर रेल पथ जड़ाई, बैलास्ट फैलाई, ओवर हेड ट्रेक्शन लाइन एवं पोल्स की मानक स्थिती तथा मार्ग में पड़ने वाले पुलों, समपार फाटकों, अंडरपासों आदि का संरक्षा निरीक्षण किया । मऊ रेलवे स्टेशन पर रेल संरक्षा आयुक्त ने यार्ड रिमाडलिंग के कार्यों के साथ पश्चिम केबिन पर वी डी यू पैनल,रिले रूम तथा खुरहट इंड पर संरक्षा गेयरों के बदलाव आदि का निरीक्षण किया और सम्बंधित से विस्तृत चर्चा की । ज्ञातव्य हो भटनी-औंड़िहार रेलखण्ड दोहरीकरण परियोजना राष्ट्रीय रेल नेटवर्क के लिए एक रणनीतिक संवर्धन है, जिसे बहुआयामी लाभ प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस परियोजना के पूर्ण होने पर, यह पूर्वोत्तर रेलवे के सबसे व्यस्त एकल-लाइन खंडों में से एक पर भीड़भाड़ को कम करेगा। रेल लाइन क्षमता में यह वृद्धि यात्री और माल ढुलाई दोनों सेवाओं के लिए उच्च गति और आवृत्ति में वृद्धि को सक्षम बनाएगी, जिससे प्रतीक्षा समय और यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी और रेल यात्रियों की सुविधा में सुधार होगा। यात्री संतुष्टि और समग्र परिचालन दक्षता में सुधार होगा। इसके अलावा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी में व्यापक सुधार करके, यह परियोजना क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति देगी । कल 18 दिसम्बर, 2025 को मऊ-खुरहट खण्ड संरक्षा निरीक्षण किया जायेगा। जिसके पश्चात रेल संरक्षा आयुक्त, उत्तर पूर्व सर्किल श्री प्रणजीव सक्सेना द्वारा स्पेशल ट्रेन से दुल्हपुर-मऊ तथा मऊ-खुरहट रेल खण्ड का अधिकतम गति से स्पीड ट्रायल भी किया जायेगा। रेल प्रशासन का दुल्लहपुर-मऊ तथा मऊ-खुरहट के आस-पास के आमजन से अनुरोध है कि निरीक्षण एवं स्पीड ट्रायल के दौरान इस रेलपथ पर न तो स्वयं जायें, न ही अपने पशुओं को रेलपथ पर जाने दें।

इस गाड़ी में एस.एल.आर. के 02 तथा शयनयान श्रेणी के 14 कोचों सहित कुल 16 कोच लगाये जायेंगे

गोरखपुरः रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु 05905/05906 डिब्रूगढ़-लखनऊ(उत्तर रेलवे)-डिब्रूगढ़ विशेष गाड़ी का संचलन डिब्रूगढ़ से 19 दिसम्बर, 2025 को तथा लखनऊ (उत्तर रेलवे) से 23 दिसम्बर, 2025 को 01 फेरे के लिये निम्नवत किया जायेगा। 05905 डिब्रूगढ़-लखनऊ (उत्तर रेलवे) विशेष गाड़ी 19 दिसम्बर, 2025 को डिब्रूगढ़ से 14.00 बजे प्रस्थान कर न्यू तिनसुकिया से 15.10 बजे, सिमालगुड़ी से 17.15 बजे, मरियानी से 18.20 बजे, फरकाटिंग से 19.25 बजे, डिमापुर से 20.50 बजे, लामडिंग से 22.30 बजे, होजाई से 23.25 बजे, दूसरे दिन चापरमुख से 00.10 बजे, जागी रोड से 00.45 बजे, गुवाहाटी से 02.40 बजे, कामाख्या से 03.00 बजे, रंगिया से 03.55 बजे, बारपेटा रोड से 05.00 बजे, न्यू बंगाईगांव से 06.10 बजे, फकिराग्राम से 06.55 बजे, न्यू कोचबिहार से 08.15 बजे, अलीपुरद्वार से 08.55 बजे, न्यू माल जं. से 11.40 बजे, सिलीगुड़ी से 13.30 बजे, न्यू जलपाईगुड़ी से 14.10 बजे, आलुआबाड़ी रोड से 15.30 बजे, किशनगंज से 16.05 बजे, बारसोई से 17.00 बजे, कटिहार से 18.40 बजे, नवगछिया से 19.32 बजे, खगड़िया से 20.52 बजे, बेगूसराय से 21.26 बजे, बरौनी जं. से 21.55 बजे, समस्तीपुर से 23.30 बजे, तीसरे दिन मुजफ्फरपुर से 00.50 बजे, हाजीपुर से 02.00 बजे, छपरा से 04.45 बजे, सीवान से 05.45 बजे, गोरखपुर से 09.20 बजे, गोंडा से 12.35 बजे तथा बाराबंकी से 14.25 बजे छूटकर लखनऊ(उत्तर रेलवे) 16.30 बजे पहुँचेगी। वापसी यात्रा में, 05906 लखनऊ (उत्तर रेलवे)-डिब्रूगढ़ विशेष गाड़ी 23 दिसम्बर, 2025 को लखनऊ (उत्तर रेलवे) से 23.30 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन बाराबंकी से 01.00 बजे, गोंडा से 02.45 बजे, गोरखपुर से 05.55 बजे, सीवान से 08.15 बजे, छपरा से 09.40 बजे, हाजीपुर से 11.40 बजे, मुजफ्फरपुर से 12.45 बजे, समस्तीपुर से 13.50 बजे, बरौनी जं. से 15.35 बजे, बेगूसराय से 16.00 बजे, खगड़िया से 16.50 बजे, नवगछिया से 18.25 बजे, कटिहार से 20.50 बजे, बारसोई से 21.55 बजे, किशनगंज से 22.55 बजे, आलुआबाड़ी रोड से 23.45 बजे, तीसरे दिन न्यू जलपाईगुड़ी से 01.30 बजे, सिलीगुड़ी से 02.05 बजे, न्यू माल जं. से 04.10 बजे, अलीपुरद्वार से 07.10 बजे, न्यू कोचबिहार से 08.00 बजे, फकिराग्राम से 09.35 बजे, न्यू बंगाईगांव से 11.10 बजे, बारपेटा रोड से 12.30 बजे, रंगिया से 13.45 बजे, कामाख्या से 14.50 बजे, गुवाहाटी से 15.35 बजे, जागी रोड से 16.40 बजे, चापरमुख से 17.15 बजे, होजाई से 18.10 बजे, लामडिंग से 19.20 बजे, डिमापुर से 21.05 बजे, फरकाटिंग से 23.10 बजे, चौथे दिन मरियानी से 00.20 बजे, सिमालगुड़ी से 01.25 बजे तथा न्यू तिनसुकिया से 03.40 बजे छूटकर डिब्रूगढ़ 05.30 बजे पहुँचेगी। इस गाड़ी में एस.एल.आर. के 02 तथा शयनयान श्रेणी के 14 कोचों सहित कुल 16 कोच लगाये जायेंगे।

गणपति फार्मा के संचालक की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी गठित

बस्ती। कोडीनयुक्त कफ सिरप के खेल में ड्रग विभाग ने हाथ खड़े कर लिए हैं। उसका कहना है कि विभाग ने अपनी भूमिका निभा दी है। एफआईआर भी दर्ज करा दी हैं। अब सारी जांच पुलिस के हाथ में है। इस काले धंधे में शामिल धंधेबाजों को सलाख के पीछे पुलिस ही पहुंचाएगी। उधर, पुलिस ने जांच तेज कर दी है। फरार गणपति फार्मा के संचालक की गिरफ्तारी के लिए एसपी अभिनंदन ने पांच सदस्यीय एसआईटी गठित कर दी गई। सूत्र बताते हैं कि गणपति फार्मा ने करीब दो करोड़ रुपये की कोडीनयुक्त कफ सिरप का कारोबार किया है। गणपति फार्मा के साथ छह फर्मों पर अब तक एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। इनमें से एक फर्म पर करीब एक महीने पहले एफआईआर दर्ज कराया गया था। एक दर्जन से अधिक मेडिकल स्टोरों को निगरानी पर रखा गया है। सूत्र बताते हैं कि गणपति फार्मा के संचालक का मोबाइल फोन लगातार बंद जा रहा है। इसके अलावा पुलिस ने उसके परिवार और कुछ रिश्तेदारों के भी मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा रखे हैं, मगर संचालक भी कम होशियार नहीं है। फरारी के दौरान उसने परिवार और रिश्तेदारों से एकदम से दूरी बना रखी है।

संदिग्ध हालात में फंदे से लटका मिला प्रधान की बेटी का शव

बस्ती। सदर कोतवाली क्षेत्र के मूडंघाट गांव की प्रधान की बेटी पूर्णिमा (26) का शव मंगलवार की सुबह कमरे में फंदे से लटका मिला। परिवार के लोग उसे मेडिकल कॉलेज ले गए जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सदर कोतवाल दिनेश चंद्र चौधरी ने बताया कि युवती का मोबाइल कब्जे में लिया गया है। परशुराम प्रजापति मूड़घाट की ग्राम प्रधान के पति परशुराम प्रजापति ने पुलिस को बताया कि पूर्णिमा की चाची मीरा कमरे के पास में गुजरीं तो उन्होंने फंदे से लटकी लाश देखकर शोर मचाया। परशुराम के मुताबिक कमरे का दरवाजा लोहे का है और उसमें ग्रिल लगा हुआ है, इसलिए कमरे के अंदर का ऊपरी हिस्सा बाहर से दिखाई देता है, इसलिए मीरा की नजर पड़ गई। मीरा के शोर मचाने पर परिवार के अन्य सदस्य भी पहुंचे। पूर्णिमा को फंदे से उतारकर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जिस साड़ी से उसने फंदा लगाया था, उसमें गांठ भी नहीं बंधी थी। मौके पर पहुंचे बड़ेवन चौकी प्रभारी ने जांच-पड़ताल कर परिवार के लोगों से पूछताछ की मगर कोई घटना की वजह नहीं बता सका।

ऑटो चालक और उसके साथी पर 50 हजार रुपये छीनने का आरोप

बस्ती। गांधीनगर निवासी अशफाक ने सदर कोतवाली क्षेत्र के कटरा पानी टंकी के पास सोमवार की दोपहर तीन बजे ऑटो चालक और उसके साथी पर 50 हजार रुपये छीनने का आरोप लगाया है। हालांकि, पुलिस इसे चोरी का मामला बता रही है। दावा किया गया है कि दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार, गांधीनगर निवासी अशफाक का आरोप है कि वह एसबीआई की गांधीनगर शाखा से 50 हजार रुपये निकालकर ऑटो से बिजली का बिल जमा करने कटरा पानी टंकी होते हुए कचहरी की तरफ जा रहे थे। कांशीराम कॉलोनी निवासी ऑटो चालक धीरू और उसका साथी बीनू सोनकर उससे किसी बात पर उलझ गए। आरोप है कि दोनों ने उसके कुर्ते का फांड़ दिया और जेब में रखे 50 हजार रुपये निकाल लिए।

कार की टक्कर से मवेशियों की मौत पर भड़के ग्रामीण

कप्तानगंज(बस्ती)। सोमवार की रात बेकाबू कार की टक्कर से दो मवेशियों की मौत पर ग्रामीण भड़क गए।हालत बिगड़ता देखकर कई थानों की फोर्स जुट गई। पुलिस के कई घंटे तक समझाने-बुझाने के बाद मामला सुलझा दिया। ग्रामीणों को मनाने में आधी रात तक पंचायत चलती रही। कप्तानगंज-टिनिच मार्ग से होकर एक बेकाबू कार सवार जा रहे थे। रात करीब 8:30 बजे जैसे ही कार सवार बेलसडे गांव के पास पहुंचे, तभी कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल को तोड़ते हुए गांव के राजेन्द्र प्रसाद की झोपड़ी में जा घुसी। झोपड़ी में बंधी एक गर्भवती भैंस की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे भैंस की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद रात करीब 10 बजे ग्रामीण उग्र हो गए। काफी देर तक पुलिस के मामले को सुलझाने का प्रयास किया लेकिन बात नहीं बनी।

जेसीबी से कुचलकर आठ साल के बच्चे की मौत, लोगों ने किया चक्काजाम

वाराणसी। वाराणसी जिले में बुधवार को दर्दनाक हादसा हुआ। एक जेसीबी से कुचलकर बच्चे की मौत हो गई। हादसे के बाद नाराज लोगों

ने सड़क जाम कर दिया। वाराणसी जिले के भेलूपुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर सब्जी मंडी के सामने हाइड्रा जेसीबी से कुचलकर आठ साल के बच्चे की मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोग और पिता इरशाद ने तत्काल बच्चे को लेकर अस्पताल गए। जहां चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को सड़क पर रखकर चक्काजाम कर दिया। उधर जानकारी होने पर मौके पर एसीपी भेलूपुर, प्रभारी निरीक्षक लंका राजकुमार शर्मा फोर्स के साथ पहुंचे और परिजनों से बातचीत करके शव को हटवाने का प्रयास किया। मुख्य मार्ग जाम होने से सुंदरपुर नरियां मार्ग पर वाहनों की कतारें लग गईं। जाम में स्कूल वाहनों में सवार बच्चे, एंबुलेंस में सवार मरीज सहित राहगीर परेशान होते रहे। कैसे हुआ हादसा जौनपुर जिले के बदलापुर थाना क्षेत्र के महाराजगंज का रहने वाला इशरत पिछले पांच वर्षों से सुंदरपुर इलाके में किराये पर पत्नी गुड़िया व दो बेटा, दो बेटियों के साथ रहकर सवारी गाड़ी चलाता है। साथ ही कैंसर संस्थान के सामने सड़क पर चाय की दुकान लगाता है। घटना में मृत बेटा इश्तियाक कक्षा 2 में पढ़ाई करता था। बुधवार सुबह मोटरसाइकिल से इश्तियाक के साथ इरशाद सब्जी लेने के लिए सुंदरपुर सब्जी मंडी पहुंचा था। मंडी में सब्जी लेने के दौरान बाइक सड़क पर खड़ी कर बेटे को बैठाया था। इस दौरान भिखारीपुर की तरफ से आ रहे हाइड्रा चालक ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। बाइक पर बैठा रियासत टक्कर लगते ही हाइड्रा के पिछले चक्के के नीचे आ गया। जिससे उसकी मौत हो गई। बच्चे को गोद में लेकर बैठे विधायक चक्का जाम होने के बाद मौके पर पहुंचे टीआई कृष्ण प्रताप यादव ने नरिया से सुंदरपुर की तरफ जाने वाले वाहनों को बैरिकेटिंग लगाकर करौदी की तरफ घुमा दिया। धरने की सूचना मिलते ही कुछ देर बाद कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंचे। विधायक बच्चे को गोद में लेकर परिजनों के साथ सड़क पर बैठ गए।

अखिलेश दुबे मुक्ति मोर्चा का संयोजक अधिवक्ता फर्जी मार्कशीट मामले में गिरफ्तार

कानपुर। अखिलेश मुक्ति मोर्चा से जुड़े आशीष शुक्ला उर्फ आशु को स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ ने उसे उत्तराखंड के नैनीताल से पकड़ा और इसके बाद कोतवाली ले जाया गया। आशीष शुक्ला के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों के जरिए लॉ करने का मामला दर्ज है, जिसकी तलाश में कोतवाली पुलिस काफी समय से जुटी हुई थी। जानकारी के अनुसार, आशीष शुक्ला पर आरोप है कि उसने फर्जी कागजातों का इस्तेमाल कर वकालत की डिग्री हासिल की थी। हाल ही में उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें अखिलेश के करीबी भूपेश अवस्थी के वीडियो के जवाब में वीडियो वायरल किया था। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और एसटीएफ ने सक्रियता बढ़ाते हुए उसकी लोकेशन ट्रेस की। लगातार निगरानी और तकनीकी सर्विलांस के बाद एसटीएफ ने नैनीताल में दबिश देकर आशीष शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे संबंधित कोतवाली में पेश किया गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। फिलहाल, पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस फजीवाड़े में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। आशीष शुक्ला को जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा।

हादसे में मृत युवक का शव रख परिजनों ने बिठूर कस्बा रोड जाम किया

कानपुर। बिठूर थाना क्षेत्र के बिहारीगंज निवासी आदित्य गिरी (18) की सोमवार देर रात ईंट के चट्टे में बाइक टकराने से मौत हो गयी थी। मामले

में निर्माण के लिए ईंट मंगवाने वाले के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगा मुआवजे के लिए परिजनों ने बुधवार को भी बिठूर कस्बे की सड़क जाम कर दी। जाम की सूचना पर बिठूर और चौबेपुर थानाप्रभारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। करीब आधे बाद परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गए। इसके पहले मंगलवार को भी जब शव पोस्टमार्टम से आया था तब भी परिजनों ने सड़क जाम कर दी थी। मामले में थानाप्रभारी इंस्पेक्टर प्रेमनरायन विश्वकर्मा ने बताया कि मंगलवार से वह परिजनों से तहरीर देने को कह रहे हैं लेकिन किसी ने तहरीर नहीं दी। तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

बाबा बिरयानी पर जाजमऊ थाने में दो करोड़ 87 लाख की ठगी की रिपोर्ट

कानपुर। जाजमऊ में एक चमड़ा कारोबारी ने बाबा बिरियानी, उसके बेटे महफूज, गुडविल टेनरी के मालिक समेत उनके साथियों पर जबरन दबाव बनाकर दो करोड़ से ज्यादा की कीमत का चमड़ा खरीदने का आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों ने चमड़ा खरीदने के बाद रकम नहीं दी और टेनरी भी बेच दी। पीड़ित ने जब भुगतान करने का दबाव बनाया तो आरोपियों ने धमकाया। पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर के आदेश पर जाजमऊ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। मुख्तार अहमद उर्फ बाबा बिरयानी नई सड़क दंगे का आरोपी भी है। घटना के बाद मुख्तार का बेटा महफूज दुबई भाग निकला।

हादसे में युवक की मौत मामले में एफआईआर

बहादुरपुर। कलवारी थाना क्षेत्र के लुंबिनी-दुद्धी मार्ग बेईली गांव के के पास 12 दिसंबर को कोहरे में तीन वाहनों के बीच हुई टक्कर में पिकअप चालक की मौत के मामले में उसकी मां ने ट्रक चालक पर एफआईआर दर्ज कराया है। नगर थाना क्षेत्र के बारीजोत की निवासी राधिका देवी में तहरीर में लिखा है कि शुक्रवार को उनका बेटा मनीष कुमार (24) गांव के पास पिकअप मोड़ रहा था। विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक के चालक ने लापरवाही पूर्वक चलाते हुए पिकअप में टक्कर मार दी थी। इससे पिकअप में बैठा उनका बेटा मनीष कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसी दिन इलाज के दौरान उसकी मौत जिला चिकित्सालय में हो गई थी।

गरिमा गृह के प्रस्ताव पर सरकार की मुहर

बस्ती। ट्रांसजेंडरों के उत्थान को लेकर इंदिरा चैरिटेबल सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय कुमार पांडेय की पहल रंग लाई। भारत सरकार ने किन्नरों के लिए जिले में दो साल पहले अजय के प्रयास पर भेजे गए गरिमा गृह के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की ओर से गरिमा गृह के स्थापना के लिए संबंधित सोसाइटी को स्वीकृति प्रदान की गई है। सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2023 से बस्ती में गरिमा गृह की स्थापना के लिए प्रयास किया जा रहा है। 2025 में सफलता मिली है। सोसाइटी द्वारा ट्रांसजेंडरों के समावेशी विकास के लिए किन्नर पाठशाला, हुनरमंद किन्नर कार्यक्रम, किन्नर कौशल विकास केंद्र, ट्रांसमित्र कार्यक्रम जैसी प्रमुख योजनाएं संचालित की जा रही है। ट्रांसजेंडरों के आत्मबल को बढ़ाने के लिए हाल ही में ट्रांसजेंडरों के मन की बात राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ कराया गया था।

बायोमेट्रिक हाजिरी पर ही मिलेगा वेतन

बस्ती। सरकारी अस्पतालों में बॉयोमैट्रिक हाजिरी अनिवार्य हो गई है। बायोमेट्रिक हाजिरी में जितने दिन उपस्थित रहेंगे, उतने दिन का ही वेतन स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगा। इस बाबत महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ने सीएमओ, जिला स्तरीय अस्पतलों के प्रमुखों को पत्र जारी किया है। पत्र में लिखकर स्वास्थ्य इकाईयों पर बायोमेट्रिक हाजिरी सुनिश्चित कराने का दिशा-निर्देश जारी दिया है। महानिदेशक की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शी व्यवस्था अपनाए जाने के लिए अधिकारी अपने नियंत्रण में संचालित अस्पतालों में तैनात चिकित्सकों व अस्पताल स्टॉफ की हर दिन की हाजिरी बायोमेट्रिक के माध्यम से दर्ज कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। उसी हाजिरी के अनुसार चिकित्सकों व अन्य स्टॉफ का मासिक वेतन जारी होगा। जानकारों का कहना है कि जिला स्तरीय अस्पतालों व सीएमओ कार्यालय में बायोमेट्रिक हाजिरी व्यवस्था पूर्व में चल रही थी। कोरोना कॉल में इसे बंद करा दिया गया था। चिकित्सकों व अन्य स्टॉफ के समय से अस्पताल न पहुंचने की लगातार शिकायत मिल रही है।

संदिग्ध हालात में फंदे से लटका मिला प्रधान की बेटी का शव

बस्ती। सदर कोतवाली क्षेत्र के मूडंघाट गांव की प्रधान की बेटी पूर्णिमा (26) का शव मंगलवार की सुबह कमरे में फंदे से लटका मिला। परिवार के लोग उसे मेडिकल कॉलेज ले गए जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सदर कोतवाल दिनेश चंद्र चौधरी ने बताया कि युवती का मोबाइल कब्जे में लिया गया है। परशुराम प्रजापति मूड़घाट की ग्राम प्रधान के पति परशुराम प्रजापति ने पुलिस को बताया कि पूर्णिमा की चाची मीरा कमरे के पास में गुजरीं तो उन्होंने फंदे से लटकी लाश देखकर शोर मचाया। परशुराम के मुताबिक कमरे का दरवाजा लोहे का है और उसमें ग्रिल लगा हुआ है, इसलिए कमरे के अंदर का ऊपरी हिस्सा बाहर से दिखाई देता है, इसलिए मीरा की नजर पड़ गई। मीरा के शोर मचाने पर परिवार के अन्य सदस्य भी पहुंचे। पूर्णिमा को फंदे से उतारकर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जिस साड़ी से उसने फंदा लगाया था, उसमें गांठ भी नहीं बंधी थी। मौके पर पहुंचे बड़ेवन चौकी प्रभारी ने जांच-पड़ताल कर परिवार के लोगों से पूछताछ की मगर कोई घटना की वजह नहीं बता सका। मामले को संदिग्ध मानते हुए पुलिस छानबीन में जुट गई है। चौकी प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

गैर इरादतन हत्या के चार दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई

बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) रामकरान यादव की कोर्ट ने मंगलवार को गैर इरादतन हत्या में चार दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

यहां झड़ते बालों के लिए मांगी जाती है दुआ, गंजेपन होता है दुर, जानें कहां है ये अनोखा मंदिर

दुनिया में कई ऐसे मंदिर हैं, जिनकी मान्यताएं लोगों को हैरान कर देती हैं। ऐसा ही एक अनोखा मंदिर जापान में स्थित है, जहां लोग धन, सुख या कहां स्थित है यह मंदिर ? मिकामी श्राइन जापान के क्योटो शहर के अराशियामा इलाके में, मशहूर बैंबू फॉरेस्ट के पास स्थित है। अपनी अनोखी मान्यता के कारण यह मंदिर इन दिनों दुनियाभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। बालों की सेहत के लिए होती है पूजा आज के समय में बाल झड़ने की समस्या आम हो गई है। ऐसे में मिकामी श्राइन उन लोगों के लिए उम्मीद की जगह बन गया है, जो हेयर फॉल और गंजेपन से परेशान हैं। यहां लोग बालों की सेहत के लिए चिट्ठी लिखते हैं और खास अनुष्ठान करते हैं। इस मंदिर की स्थापना 1960 में हुई थी। मिकामी श्राइन को फुजीवारा उनेमेनोसुके मसायुकी को समर्पित किया गया है, जिन्हें जापान का पहला हेयरड्रेसर माना जाता है। उनके सम्मान में आज भी जापान के कई नाई और हेयर सैलून हर महीने 17 तारीख को अपनी दुकानें बंद रखते हैं।

संक्षिप्त समाचार

प्राधिकरण मेला व्यापारियों के प्लॉटों पर अतिक्रमण को रोके

ग्वालियर। मेला व्यापारी संघ के अध्यक्ष महेन्द्र भदकारिया एवं सचिव महेश मुदगल ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से मेला प्राधिकरण पर आरोप लगाते हुए कहा है कि व्यापारियों को आवंटित भूमि पर कतिपय तत्व अतिक्रमण कर रहे हैं। एक-दूसरे के प्लॉट में घुसपैठ हो रही है। विरोध या शिकायत करने पर वाद-विवाद की नौबत और हुड़दंग की स्थिति पैदा हो जाती है। यह स्थिति मेला प्राधिकरण के कर्ताधर्ताओं द्वारा दुकानदारों को आवंटित प्लॉटों एवं खुली भूमि का सीमांकन नियमोचित व निष्पक्ष ढंग से न करने के कारण बनी है। यदि किसी भी दुकानदार या व्यापारी के प्लॉट में अतिक्रमण की शिकायत आती है तो मेला प्राधिकरण को तत्काल हस्तक्षेप कर कब्जाई गई जमीन को मुक्त कराकर मूल आवंटी को पूरे प्लॉट का कब्जा दिलाना चाहिए जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। व्यापारी संघ ने कहा है कि मेला पार्किंग और अन्य गेटों को खोला जाए जिससे सैलानियों का प्रवेश सुगम ढंग से हो सके।

युवक ने फांसी लगाकर दी जान

ग्वालियर। एक युवक ने अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। घटना जनकगंज थाना क्षेत्र के संजय नगर में मंगलवार की दोपहर तीन बजे की है। घटना का पता उस समय चला जब परिजनों ने उसे फंदे पर लटके देखा। मामले का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर शव को शव विच्छेदन गृह पहुंचा दिया। जनकगंज थाना क्षेत्र के गोल पहाड़िया स्थित संजय नगर निवासी 22 वर्षीय आकाश पुत्र हरिसिंह कुशवाह निजी कंपनी में काम करता था। मंगलवार को वह अपने कमरे में पहुंचा और फांसी लगाकर जान दे दी। फिलहाल पता नहीं चला है कि मृतक ने किन कारणों के चलते फांसी लगाकर जान दी है। पुलिस अब पता लगा रही है कि उसके आत्महत्या करने के पीछे क्या कारण है।

पवन शर्मा संभागीय कार्यकारी अध्यक्ष बने

ग्वालियर। मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की संभागीय कार्यकारिणी प्रदेश महामंत्री जितेंद्र सिंह ने घोषित की है। कार्यकारिणी में ग्वालियर के शासकीय हाईस्कूल खड़ीखेड़ा के प्रयोगशाला सहायक पवन शर्मा को संभागीय कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया है।

निरीक्षण में गायब मिले कर्मचारियों को नोटिस

ग्वालियर। शहर की साफ-सफाई व्यवस्था की पोल उस समय खुल गई जब अपर आयुक्त स्वास्थ्य टी. प्रतीक राव ने मंगलवार सुबह शहर के विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया। नगर निगम क्षेत्र में चल रहे प्रात :कालीन डोर-टू-डोर वाहन सत्यापन अभियान के दौरान कई अधिकारी और वाहन चालक बिना किसी पूर्व सूचना के अपने निर्धारित स्थानों से गायब मिले। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ वाहन चालक तय समय सुबह 7 :30 बजे की बजाय 8 बजे और कहीं-कहीं 8 :45 बजे तक काम शुरू कर रहे थे। इस लापरवाही के चलते अभियान की पूरी व्यवस्था चरमराई नजर आई। अनुशासनहीनता मानते हुए निगम प्रशासन ने मौके पर ही संबंधित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दे दिए। पूर्व और दक्षिणी वार्डों में स्थिति सबसे ज्यादा खराब पाई गई। यहां कई वाहन चालक पूरे समय अनुपस्थित रहे, जबकि कुछ निर्धारित समय से डेढ़ घंटे देरी से पहुंचे। यही नहीं, वार्ड क्रमांक 03 और 06 में पदस्थ कई कर्मचारियों को भी ड्यूटी से गायब पाया गया।

स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया पर हाथ ठेलों का जमावड़ा, यात्रियों की राह मुश्किल

■डीआरएम के आदेश की अवहेलना

■ ग्वालियर

रेलवे स्टेशन का सर्कुलेटिंग एरिया रोजाना हजारों यात्रियों की आवाजाही का सबसे संवेदनशील इलाका है, लेकिन यहां हालात अब पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं। एक तरफ स्टेशन पुनर्विकास का काम तेजी से चल रहा है, तो दूसरी तरफ अतिक्रमण ने यात्रियों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। स्टेशन का मुख्य प्रवेश द्वार बंद है, वैकल्पिक व्यवस्था नाकाफी है और सर्कुलेटिंग एरिया में अवैध ठेले इस कदर फैल चुके हैं कि यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं रह गया है।

मुख्य प्रवेश द्वार के आसपास सबसे ज्यादा जाम की स्थिति बन रही है। ऑटो, टैक्सी, निजी वाहन और पैदल यात्रियों के बीच ठेले वालों ने पूरी तरह कब्जा जमा लिया है। दिन ढलते ही हालात और बदतर हो जाते हैं। रात के समय ठेलों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है और पूरा सर्कुलेटिंग एरिया अवैध बाजार में तब्दील हो जाता है। दोपहर में भी स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ रही है, जब यात्रियों की संख्या चरम पर होती है।

अधिकारी बने मूक दर्शक

स्टेशन पर मौजूद स्थानीय रेलवे अधिकारी बाहर निकलकर एक बार भी यह देखने की जहमत नहीं उठा रहे कि जाम क्यों लग रहा है और यात्री कहां फंस रहे हैं। न तो कोई अस्थाई ट्रैफिक प्लान बनाया गया है और न ही यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने के लिए कोई स्पष्ट मार्ग तय किया गया है। स्टेशन प्रशासन मानो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़े बैठा है।

मंडल रेल प्रबंधक जता चुके नाराजगी

मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार ने कुछ दिन पहले स्टेशन का निरीक्षण किया था। सर्कुलेटिंग एरिया में खड़े ठेलों को देखकर उन्होंने मौके पर ही सख्त नाराजगी जताई और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि अवैध ठेलों को तुरंत हटाया जाए। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि कार्रवाई में कोई बाधा आती है तो एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि डीआरएम के लौटते ही हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो गए।

बिना डर के खुलेआम खड़े हो रहे ठेले

अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी साफ तौर पर आरपीएफ और वाणिज्य विभाग की है। आरपीएफ को स्टेशन परिसर की सुरक्षा और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि वाणिज्य विभाग को स्टेशन के उपयोग और व्यवस्था का नियंत्रण सौंपा गया है। इसके बावजूद दोनों विभाग जमीन पर कहीं सक्रिय नजर नहीं आते। ठेले बिना किसी डर के खुलेआम खड़े हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जीआरपी थाने के ठीक बगल में भी ठेले धड़ल्ले से लग रहे हैं।

इनका कहना है

सर्कुलेटिंग एरिया में अगर अवैध रूप से ठेले खड़े हो रहे है तो उन्हें तुंरत हटाया जाएगा।

मनोज कुमार सिंह
जनसंपर्क अधिकारी
झांसी मंडल

कांग्रेस के नौ ब्लॉक अध्यक्ष घोषित, नहीं चली अध्यक्ष की

■ ग्वालियर

कांग्रेस में भले ही राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान चलाकर जिला और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियों की बात कही है, लेकिन मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा घोषित ब्लॉक अध्यक्षों को लेकर विवादित स्थिति बन गई है। यही कारण है कि मनरेगा को लेकर 17 दिसंबर को दिए जाने वाले धरने की तिथि आगे बढ़ाना पड़ी है। ग्वालियर में भी ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियों में विवाद के कारण ग्वालियर विधानसभा के अध्यक्ष घोषित नहीं किए जा सके। वहीं ग्वालियर पूर्व में भी एक ब्लॉक अध्यक्ष को होल्ड पर रखना पड़ा है। इस तरह दो विधानसभाओं में दस की जगह नौ ब्लॉक अध्यक्ष घोषित किए गए हैं।खास बात यह है कि इनमें शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र यादव अपनी पसंद का एक भी ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बनवा सके।

देर रात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश भर के ब्लॉक अध्यक्षों की लंबी चौड़ी सूची जारी की है। इसमें ग्वालियर दक्षिण के पांच ब्लाक अध्यक्ष गोल पहाड़िया लक्ष्मी माथुर,राम मंदिर कुलदीप व्यास, हेमू कालानी श्यामसुंदर श्रीवास्तव,कंपू हरि जाटव और माधवगंज से अंसार खां को बनाया गया है। इसमें राम मंदिर ब्लॉक का अध्यक्ष तरुण यादव को बनवाने के लिए पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, रश्मि पवार शर्मा और राहुल शर्मा ने एड़ी चोटी का जोर लगाया लेकिन सभी पांच अध्यक्ष पूर्व विधायक एवं प्रदेश महासचिव प्रवीण पाठक की पसंद के बनाए गए हैं। वहीं ग्वालियर पूर्व में चार ब्लॉक अध्यक्षों में इंदरगंज से अनूप शिवहरे, थाटीपुर से संदीप यादव,गोला का मंदिर से राजेश तोमर और मेला ग्राउंड से रेखा जाटव को बनाया है। यह सभी विधायक डॉ सतीश सिकरवार की पसंद के हैं जबकि मुरार ब्लॉक को लेकर पेंच फंस गया है। यहां से सतीश सिकरवार, विनोदी जैन को रिपीट कराना चाहते हैं, जबकि राज्यसभा सदस्य अशोक सिंह एवं जिला अध्यक्ष सुरेंद्र यादव की पसंद सौरभ जैन है।इसी कारण इसे होल्ड करना पड़ा है।

ग्रामीण में साहब सिंह के नाम

ग्वालियर ग्रामीण से चार ब्लॉक अध्यक्ष घोषित हुए हैं इसमें पुरानी छावनी से अतर सिंह यादव,बेरजा से केदार कौशल, छावनी केंट से साहब सिंह बघेल और हस्तिनापुर से कल्याण सिंह गुर्जर के नाम है। यह विधायक साहब सिंह की पसंद के हैं।

ग्वालियर में मीतेंद्र-नाती का पेंच

ग्वालियर विधानसभा में पांच में से एक भी ब्लॉक अध्यक्ष घोषित नहीं हो सके। कारण प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा और शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र यादव ने जो नाम दिए थे उसमें युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मीतेंद्र दर्शन सिंह एवं राजेन्द्र सिंह नाती ने अपने पसंदीदा नाम देकर पेंच लगवा दिया। सुनील शर्मा अपनी विधानसभा में पांच में से चार ब्लॉक अध्यक्ष अपने चाहते हैं लेकिन मीतेंद्र कम से कम दो नामों पर अड़ गए हैं इसी तरह नाती भी दो नाम चाहते हैं। जिससे यह विधानसभा होल्ड कर दी गई है।

शादी में गए परिजन, खाली घर से चोरों ने उड़ाए जेवर और नकदी

■ ग्वालियर

सिरौल थाना क्षेत्र के अंकलेश्वर एवेन्यू में चारों ने उस समय वारदात को अंजाम दिय जब घर के लोग आगरा शादी समारोह में शामिल होने गए थे और घर भतीजे के भरोसे छोड़ गए थे। भतीजा पढ़ाई करने के लिए चला गया। इस बीच चोरों को मौका मिल गया। ताला तोड़कर चोर घर में रखी नकदी व सोने-चांदी के जेवरात पार कर ले गए। शादी से गृह स्वामी वापस आए तो घटना का पता चला।

चंद्रशेखर जाटव निवासी अंकलेश्वर एवेन्यू सिरोल 10 दिसम्बर को परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने के लिए आगरा गए थे। घर पर कोई नहीं था, इसलिए वह मुरार में रहने वाले अपने भतीजे को घर की जिम्मेदारी सौंप कर गए थे। भतीजा पढ़ाई करता है इसलिए 11 दिसम्बर को वह भी चला गया। घर में ताले लटकते देख चोरों को मौका मिल गया और वह ताले तोड़कर अंदर पहुंच गए। अलमारी का ताला तोड़ा तो उसमें नकद रुपए मिले। चोरों ने कमरों में रखे पलंग की तलाशी ली तो उसमें सोने-चांदी के जेवर रखे थे वह ले गए। चंद्रशेखर 14 दिसम्बर को आगरा से वापस आए तब घटना का पता चला। सिरौल पुलिस जांच करने पहुंची तो घर का पूरा सामान अस्त-व्यस्त पाया। पुलिस ने फोटोग्राफी की और फिंगरप्रिंट लिए। आस-पास लगे सीसीटीवी को देखने के बाद अभी तक कुछ पता नहीं चला है।

फर्जी संपत्तिकर आईडी खत्म करें, बिना मोबाइल नंबर वाली आईडी अपडेट कराएं

■ ग्वालियर

जिन संपत्तिकर आईडी में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं हैं, उनमें तत्काल नंबर अपडेट कराए जाएं। अब तक बनी सभी फर्जी आईडी का सत्यापन कर उन्हें समाप्त किया जाए। लक्ष्य के अनुरूप संपत्तिकर की वसूली हर हाल में सुनिश्चित की जाए। यह निर्देश मंगलवार को निगमायुक्त संघ प्रिय ने रेस कोर्स रोड स्थित क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक-10 के औचक निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को दिए। इस दौरान उन्होंने यह जानकारी ली कि क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत कुल कितनी संपत्तियां दर्ज हैं, चालू वित्तीय वर्ष में कितना संपत्तिकर वसूल किया गया है और कितना बकाया शेष है।

निरीक्षण के दौरान निगमायुक्त ने क्षेत्रीय कार्यालय में कर्मचारियों की उपस्थिति भी जांची। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कर्मचारी शत-प्रतिशत और समय पर कार्यालय में उपस्थित रहें। इसके साथ ही कार्यालय परिसर में साफ-सफाई बनाए रखने और आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए गए। निगमायुक्त ने कहा कि मोबाइल नंबर अपडेट होने से करदाताओं से संवाद बेहतर होगा और बकाया राशि की वसूली में भी आसानी होगी। वहीं फर्जी आईडी खत्म होने से निगम की आय में वास्तविक वृद्धि संभव हो सकेगी। औचक निरीक्षण के दौरान उपायुक्त डॉ. प्रदीप श्रीवास्तव, प्रभारी राजस्व निरीक्षक शशिकांत शुक्ला सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर आज

■ ग्वालियर

लॉयंस क्लब ग्वालियर राइजिंग और दिव्य दृष्टि नेत्रालय एवं लेजर सेन्टर द्वारा निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन शिविर का आयोजन बुधवार 17 दिसंबर को प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक पुराना हाईकोर्ट स्थित दिव्य दृष्टि नेत्रालय एवं लेजर हॉस्पिटल में आयोजित किया जाएगा। जिसमें नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. विजय आहूजा एवं उनकी टीम द्वारा परीक्षण और ऑपरेशन किए जाएंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुधीर वाजपेयी, विशिष्ट अतिथि नितिन मांगलिक एवं विकास गंगवाल होंगे।

दहेज हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

■ ग्वालियर

दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने और पेट्रोल डालकर आग लगाकर उसकी हत्या करने के आरोपी पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं 2 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक मिनी शर्मा ने बताया कि घटना 18 अप्रैल 2017 से 19 जुलाई 2021 की है। जिसमें 19 जुलाई 2021 को आरोपी गोविंद खटीक पुत्र पप्पू लाल खटीक निवासी रामदास घाटी ने अपनी पत्नी माधवी खटीक को पेट्रोल डालकर जला दिया। इस मामले में बहोड़ापुर थाना के उप निरीक्षक दयाराम शर्मा ने अस्पताल जाकर माधवी के मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किए। जिसमें उसने बताया कि वह अपने

ससुराल सुनारों की बगिया में पति के साथ रहती थी। उसका विवाह गोविंद खटीक के साथ 18 अप्रैल 2017 को हुआ। उसके एक तीन साल की बच्ची है। पति गोविंद द्वारा अक्सर दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। 19 जुलाई 2021 को दोपहर 2 बजे पैसों के विवाद पर उसने पेट्रोल पीने को दिया। मना करने पर पूरे शरीर पर उड़ेल दिया और माचिस से आग लगा दी। उसे जेठानी रत्ना ने जयारोग्य अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में गोविंद ने उसे धमकी दी कि वह पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराए नहीं तो वह साथ में नहीं रखेगा। जहां उसकी 25 जुलाई को मौत हो गई। जिस पर बहोड़ापुर थाना पुलिस ने गोविंद खटीक और उसके दो मित्रों शैलू उर्फ शैलेन्द्र खटीक एवं मनीष खटीक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की। विशेष न्यायालय ओएडब्ल्यू एवं सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रिद्धि मिश्रा ने सुनवाई के बाद मुख्य आरोपी पति गोविंद खटीक को दोषसिद्ध ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय सुनाया। सह अभियुक्त शैलेन्द्र खटीक को दोषमुक्त करार दिया गया जबकि एक अन्य सह अभियुक्त मनीष खटीक के फरार होने से उसके खिलाफ मुकदमा जारी रहेगा।

डॉ. राजेश जैन इंस्पायरिंग लीडर अवार्ड से सम्मानित

■ ग्वालियर

एमिटी विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. राजेश जैन को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान एवं प्रेरणादायी नेतृत्व के लिए ईजीएन ग्रुप द्वारा इंस्पायरिंग लीडर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान 13 दिसंबर को इंदौर में एक होटल में आयोजित ईजीएन एजुकेशन लीडरशिप समिट एंड अवार्ड्स समारोह में प्रदान किया गया। समारोह के दौरान डॉ. जैन को विशिष्ट वक्ता के रूप में भी आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने स्किलिंग, अप-स्किलिंग एवं री-स्किलिंग उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका विषय पर आयोजित राउंड टेबल चर्चा में अपने विचार साझा किए।

इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में देशभर से शिक्षाविदों, नीति-निर्माताओं एवं उद्योग विशेषज्ञों ने सहभागिता की। डॉ. जैन की इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय के प्रो-चांसलर वीके.शर्मा, कुलगुरु डॉ. आरएस तोमर, प्रो-वाइस चांसलर डॉ. एमपी कौशिक सहित समस्त विश्वविद्यालय परिवार ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी।

सातवें वेतनमान की मांग को लेकर जीविवि के स्थाई कर्मियों का चरणबद्ध आंदोलन 24 से

■ ग्वालियर

सातवें वेतनमान की मांग को लेकर जीवाजी विश्वविद्यालय के स्थाई कर्मचारी संघ ने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। मंगलवार को गालव सभागार में हुई साधारण सभा की बैठक में यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

संघ के अध्यक्ष यतेन्द्र शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट का आदेश मिलने के बाद 26 नवंबर को दिए गए ज्ञापन पर निर्वतमान कुलसचिव प्रो. राकेश कुशवाह ने विवि स्तर पर वेतनमान देने का आश्वासन दिया था पर उन्होंने 28 नवंबर को एक पत्र उच्च शिक्षा आयुक्त को भेज दिया। जिसमें लिखा कि स्थाईकर्मी योजना के तहत वेतनमान भी शासन द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण पर शासन द्वारा निर्णय लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को मार्गदर्शन प्रदान करें। कुलसचिव की इस वादाखिलाफी पर कर्मचारियों ने एक सुर में कहा कि हाईकोर्ट में निर्णय होने के बाद भी कर्मचारियों की जायज मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके बाद सर्वसम्मति से तय हुआ कि यदि विश्वविद्यालय के कुलगुरु व नवागत कुलसचिव प्रो. राजीव मिश्रा सात दिन के अंदर सातवें वेतनमान का लाभ नहीं दिलाते तो 24 दिसंबर से स्थाई कर्मचारी चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। बैठक में उपाध्यक्ष प्रशांत सिंह, सचिव द्वारका प्रसाद झा, संयुक्त सचिव जयराम रजक, कोषाध्यक्ष दिलीप कुशवाह सहित कार्यकारिणी सदस्य व कर्मचारी उपस्थित रहे।

एमएलबी कॉलेज में शुरू हुई नेट-जेआरएफ व सेट परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग

■ ग्वालियर

महारानी लक्ष्मीबाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ एवं आइक्यूएसी के संयुक्त तत्वावधान में विद्यार्थियों के लिए नेट जेआरएफ और सेट की परीक्षा की तैयारी हेतु निःशुल्क तीन सप्ताह की कोचिंग शुरू की। इसका शुभारंभ करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. हरीश कुमार अग्रवाल ने कहा कि नेट-जेआरएफ एवं सेट की आगामी परीक्षाओं के लिए यह कोचिंग मील का पत्थर साबित होगी। कोचिंग में 130 विद्यार्थियों ने अपना पंजीयन कराया। कोचिंग 16 दिसंबर से 03 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। उद्घाटन कार्यक्रम में डॉ. डीएस राणा, डॉ. विभा दुर्वार, डॉ भारती कार्णिक, डॉ संजय गुप्ता, डॉ जितेंद्र श्रीवास्तव, डॉ रवि शंकर पाठक उपस्थित हुए। कार्यक्रम का संचालन डॉ. अनीता मेवाफरोश ने एवं आभार डॉ. एके मांडिल ने किया।

एनटीएफ गाइडलाइंस का हर हाल में पालन कराने जिलाधीश के कड़े निर्देश

विद्यार्थियों की आत्महत्या रोकने जिला टास्क फोर्स गठित

■ ग्वालियर

विद्यार्थियों में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति को गंभीर चुनौती मानते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत गठित नेशनल टास्क फोर्स (एनटीएफ) के अंतर्गत ग्वालियर जिले में डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स (डीटीएफ) का गठन कर दिया गया है। जिला स्तरीय टास्क फोर्स की पहली बैठक जिलाधीश रुचिका चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित

हुई, जिसमें लापरवाही बरतने वाले शिक्षण व कोचिंग संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए गए।

जिलाधीश श्रीमती चौहान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य किसी भी स्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। एनटीएफ की गाइडलाइंस का पालन सभी शासकीय, अशासकीय शिक्षण संस्थानों एवं कोचिंग सेंटरों में अनिवार्य रूप से और समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी संस्थान एनटीएफ की वेबसाइट पर तत्काल पंजीयन कराएं और सर्वे प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में जिला टास्क फोर्स की सदस्य सचिव एवं अग्रणी महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. सरिता श्रीवास्तव ने एजेंडा प्रस्तुत करते हुए बताया कि जिले के सभी कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों का पंजीयन, प्रशासनिक रजिस्ट्रेशन, मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम की स्थापना तथा व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अधिकांश शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों द्वारा पंजीयन पूरा कर लिया गया है और सर्वे प्रक्रिया जारी है, जिसे और तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में जिला पंचायत सीईओ सोजान सिंह रावत, अपर कलेक्टर कुमार सत्यम, एडीएम सीबी प्रसाद सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

बाप-बेटे पर ब्लेड से हमला कर गल्ले से रुपए लूटकर भागा बदमाश

■ ग्वालियर

फोटो स्टूडियो की दुकान पर बैठे बाप-बेटे पर एक बदमाश ने ब्लेड से हमला कर घायल कर लिया। हमला करने के बाद वह उनके गल्ले से रुपए भी लूटकर ले गया।

हालांकि पीड़ितों ने उसका पीछा किया, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाश को तलाशा, लेकिन वह हाथ नहीं आया। सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो बदमाश नजर आ गया। फिलहाल थाटीपुर थाने में मामला दर्ज कर बदमाश की तलाश की जा रही है। थाटीपुर थाना क्षेत्र के गला कोठार में रहने वाले करतार सिंह और उनके बेटे पर हमला हुआ है। उनकी गौतम नगर में फोटो स्टूडियो की दुकान है। करतार सिंह अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। उनका बेटा कंप्यूटर पर काम कर रहा था। तभी दुकान में अनिकेत नाम का बदमाश पहुंचा। वह कुछ समझ पाते उससे पहले उसने उन पर ब्लेड से हमला कर दिया। पिता चिल्लाए तो बेटा बाहर आया तो बदमाश ने उस पर भी ब्लेड से हमला कर दिया। इस हमले में पिता के हाथ और बेटे के सिर में चोट आई है। पीड़ितों ने बताया कि बदमाश गल्ले में रखे 1200 रुपए भी निकालकर भागा है। हालांकि करतार के बेटा ने उसे पकड़ने का प्रयास किया लेकिन कामयाब नहीं हो सका। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज देखे तो आरोपी भागता हुआ नजर आ रहा है।

मंत्र भारत
ग्वालियर-गुरूवार,18 दिसम्बर 2025

संपादकीय

अमीरी दे गरीब को त्रास

देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली घातक पर्यावरण संकट झेल रही है। विडंबना यह है कि इस संकट के निदान के लिये जो उपाय लागू किए जा रहे हैं, उसका खमियाजा गरीबों को झेलना पड़ रहा है। इस संकट की संवेदनशीलता को महसूस करते हुए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि अमीरों की जीवन शैली से उपजी मुश्किलों का सामना गरीबों को करना पड़ता है। दरअसल, बिगड़ते प्रदूषण संकट के बाबत दायर याचिकाओं को आज सुनवाई के लिये सूचीबद्ध करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने यह मर्मस्पर्शी टिप्पणी की। कोर्ट ने भरोसा दिलाया कि वह इस बाबत प्रभावी और लागू करने योग्य आदेश पारित करेगा। दरअसल, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने वरिष्ठ वकील और न्यायमित्र अपराजिता सिंह की दलीलों पर गौर करते हुए ये टिप्पणी की थी। अदालत का कहना था कि दिल्ली एनसीआर में ग्रेप-4 लागू करने के चलते जो पाबंदियां लागू की गई हैं, उनका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब लोगों को हो रहा है। इससे निर्माण कार्य बंद होने से हजारों गरीब मजदूरों का चूल्हा नहीं जल सकेगा। मुख्य न्यायाधीश ने इस बाबत कहा कि संपन्न लोगों को अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए। साथ ही कहा कि हमें समस्या का पता है और इसलिए हम ऐसे आदेश पारित करेंगे, जिनका पालन किया जा सकेगा। कहा कि कुछ निर्देश ऐसे भी हैं, जिन्हें बलपूर्वक लागू किया जा सकता है। जस्टिस सूर्यकांत का कहना था कि महानगरों में लोगों की अपनी अलग जीवनशैली होती है, जिन्हें वे बदलना नहीं चाहते। यही वजह है कि समस्या अमीरी की वजह से होती है, लेकिन झेलना गरीब को पड़ता है। दरअसल, अदालत की सोच रही है कि हमारा परिवेश-पर्यावरण साफ-सुथरा रहे, इसके लिये हम सबको अपने कुछ सुखों का त्याग करना होगा। यह जानते हुए कि पर्यावरण पर आने वाले संकट व प्रदूषित हवा का अमीर-गरीब पर समान असर पड़ता है। निस्संदेह, देश की शीर्ष अदालत ने देश व समाज की दुखती रग पर ही हाथ रखा है। महानगरों में अमीर तबके की विलासिता के चलते ही पर्यावरण व अन्य संकटों को बढ़ावा मिलता है। महानगरों में लगातार सड़कों का विस्तारीकरण, नए हाइवे निर्माण व ओवर ब्रिज निर्माण के बावजूद जाम व प्रदूषण का संकट कम नहीं हो रहा है। दरअसल, हमने अपनी सुख-सुविधाओं को प्राथमिकता दी है, लेकिन व्यापक सामाजिक हितों की अनदेखी की है। आमतौर पर एक अकेले व्यक्ति के लिये कारें सड़कों पर दौड़ती रहती हैं। जो न केवल सड़कों में ज्यादा जगह घेरती हैं, बल्कि ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करके प्रदूषण को भी बढ़ावा देती हैं। यही वजह है कि आम आदमी सरकार ने अपने कार्यकाल में ऑड-इवन प्रणाली शुरू करने को प्राथमिकता दी थी ताकि सड़कों पर कारों का सैलाब कम किया जा सके। तब बात उठी थी कि एक दिशा में और एक ऑफिस की तरफ जाने वाले लोग कार शेयर करके चलें। विडंबना यह है कि सत्ताधीशों ने दिल्ली में सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट को सशक्त करने को प्राथमिकता नहीं दी। यदि सार्वजनिक परिवहन सस्ता व सहज उपलब्ध होता तो शायद सड़कों पर कारों का दबाव कम होता। हाल के दिनों में संपन्न व मध्यम वर्ग में एसी व अन्य वातानुकूलन उपायों के उपयोग का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। इससे जहां प्रदूषण बढ़ाने वाली बिजली की खपत बढ़ी है, वहीं बाहर का तापमान व कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ा है। इसी तरह तमाम अमीरों द्वारा संचालित उद्योगों में उन उपायों का ईमानदारी से पालन नहीं किया गया जो पर्यावरण में प्रदूषण कम करने में सहायक होते हैं। विडंबना यह है कि महानगरों व अन्य शहरों में जहां कुछ इलाकों में पेयजल का संकट बना रहता है, वहीं दूसरे पॉश इलाकों मे लॉन सींचने, कार धोने और स्वीमिंग पूलों के लिये पर्याप्त पानी उपलब्ध रहता है। अकसर कहा जाता है कि कुदरत ने हर व्यक्ति के लिए हवा, पानी व भोजन उपलब्ध कराया है, लेकिन इनके असमान वितरण व अमीरी के दखल के चलते, गरीब के साथ न्याय नहीं हो पाता है। अमीर होना बुरा नहीं है लेकिन उसकी अमीरी की कीमत गरीब को न चुकानी पड़े।

मनरेगा से जी राम जी, भाजपा की सनक

> बल्कि इसमें काम के दिनों से लेकर केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय व्यवस्था को भी बदल दिया है। जिसके बाद एक बार फिर से मोदी सरकार की नीयत पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर मनरेगा को बदलने के पीछे क्या मंशा ग्राम पंचायतों से अधिकार छीनने और उन्हें कमजोर करने की है।ज्ञात हो कि मंगलवार को मोदी सरकार ने लोकसभा में श्विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण 2025श पेश किया। इसका संक्षिप्तीकरण वी बी- जी राम जी के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है। राम शब्द का सियासी इस्तेमाल कितने तरीकों से किया जा सकता है, इसकी नयी-नयी मिसालें मोदी सरकार पेश कर रही है। राम मंदिर बनाने के लिए रथ यात्रा निकालने से लेकर बाबरी मस्जिद गिराकर उस जगह पर राम मंदिर के लिए पहले शिलान्यास करना, फिर राम मंदिर बनने के बाद उद्घाटन करना और इसके बाद मंदिर में धर्म ध्वजा फहराने जैसे काम किए गए, इसके बाद भी भाजपा को लगता है

नाम बदलना भाजपा का पुराना शगल रहा है। सड़कों, स्टेशनों, चौराहों के साथ-साथ पुरानी सरकारों की शुरू की गई बहुत सी योजनाओं के नाम भाजपा सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन इस बार मोदी सरकार ने एक ऐसी योजना पर राजनीति की है, जो ग्रामीण भारत की आजीविका के लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण

रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा का न केवल नाम बदला है, बल्कि इसमें काम के दिनों से लेकर केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय व्यवस्था को भी बदल दिया है। जिसके बाद एक बार फिर से मोदी सरकार की नीयत पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर मनरेगा को बदलने के पीछे क्या मंशा ग्राम पंचायतों से अधिकार छीनने और उन्हें कमजोर करने की है।ज्ञात हो कि मंगलवार को मोदी सरकार ने लोकसभा में श्विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण 2025श पेश किया। इसका संक्षिप्तीकरण वी बी- जी राम जी के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है। राम शब्द का सियासी इस्तेमाल कितने तरीकों से लगता है कि राम नाम को भुनाने की संभावनाएं अभी मौजूद हैं, लिहाजा अब महात्मा गांधी के नाम पर पिछले 20 सालों से चल रही ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को ही बदल दिया गया है।पिछले सप्ताह तक चर्चा थी कि भाजपा मनरेगा में महात्मा गांधी की जगह पूज्य बापू करना चाहती है। इस पर भी विपक्ष ने सवाल किया था कि आखिर महात्मा गांधी नाम से भाजपा को क्या तकलीफ है। लेकिन अब तो न केवल महात्मा गांधी शब्द हटाया गया है, बल्कि योजना ही बदलने की तैयारी है। जिसके बाद संसद का शीतकालीन सत्र में बड़ा विवाद बन गया है। विपक्ष ने मंगलवार को संसद परिसर में इस पर प्रदर्शन भी किया। प्रणिति शिंदे और कुमारी शैलजा समेत कुछ सांसद तो पुराने संसद भवन की छत पर चढ़कर गांधीजी के पोस्टर के साथ नारेबाजी करते दिखे।दरअसल मनरेगा को बदलने का यह प्रस्ताव ग्रामीण भारत की आजीविका से जुड़ा होने के कारण राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरीके से संवेदनशील है। पांच साल पहले जब कोरोना की महामारी ने देश को आर्थिक तौर पर भी झकझोर कर रख दिया था, तब इसी मनरेगा के कारण ग्रामीण भारत में दो वक्त की रोटी का सहारा बना रहा। केंद्र की मोदी सरकार ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है और माना है कि मनरेगा से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा मिला है। जबकि अपने पहले कार्यकाल में इसी मनरेगा का मजाक उड़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इसे यूपीए सरकार का गड्ढा बताया था। जबकि मनरेगा इतना क्रांतिकारी कानून था कि 2005 में जब इसे लाया गया था, तब संसद में सभी राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया था।मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार को साल में 100 दिन के मजदूरी वाले काम की गारंटी देता है। जबकि नए विधेयक में मजदूरी के 125 दिन निर्धारित किए गए हैं, लेकिन इसमें न मानदेय बढ़ाया गया है, न ये तय है कि ग्रामीण किस तरह रोजगार की गारंटी पाएंगे, क्योंकि अब यह हक ग्राम पंचायतों का नहीं केंद्र का हो जाएगा। प्रियंका गांधी ने इस बारे में लोकसभा में कहा है कि मनरेगा मांग-आधारित है, जिसमें केंद्र सरकार की फंडिंग भी मांग के अनुसार होती है। लेकिन नए विधेयक में केंद्र नॉर्मेटिव फंडिंग के आधार पर वित्तपोषण करेगा। नॉर्मेटिव फंडिंग मतलब एक ऐसी प्रणाली जहां धन का आबंटन पूर्व-निर्धारित मानकों, मानदंडों या नियमों के आधार पर होगा, ग्राम सभा की जरूरत के मुताबिक नहीं। यानी किसी ग्राम सभा को अगर किसी कार्य के लिए ज्यादा धन की जरूरत होगी, तब भी केंद्र उसे वह मुहैया नहीं कराएगा, बल्कि जो पहले से तय है, उतना ही फंड जारी करेगा। इससे ग्राम सभाओं की भूमिका कमजोर होगी, जो स्थानीय स्तर पर काम की मांग तय करती हैं। प्रियंका गांधी ने चेतावनी दी है कि श्रोजगार का अधिकार कमजोर किया जा रहा है, जो हमारे संविधान के खिलाफ है।श जी राम जी में अधिकांश राज्यों के लिए केंद्र का फंड योगदान 60 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है, जबकि राज्यों को पहले से जीएसटी की बकाया राशि भी नहीं मिल रही है, ऐसे में ग्रामीण रोजगार के लिए धन की कमी राज्यों में हो जाएगी और इसका नुकसान उन ग्रामीणों को भुगतना पड़ेगा, जिनके घर मनरेगा के कारण चल रहे हैं। प्रियंका गांधी ने इस फैसले को श्सनकश बताते हुए कहा कि इससे हर बार सरकारी खजाने पर बोझ पड़ता है। क्योंकि नाम बदलने में सरकारी खर्च भी होता है। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि आज की महंगाई में मानदेय कैसे बढ़े और इस योजना से किसान को कैसे जोड़ा जाए, यह देखना चाहिए...आप पूरा भार राज्य सरकार पर डाल देंगे। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं होगा।वहीं मोदी सरकार में शामिल तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी ने भी जी राम जी योजना पर चिंता जताई है। टीडीपी का कहना है कि श्इस योजना में वित्त पोषण की जो नयी व्यवस्था बनाई गई है, उससे राज्य सरकार पर बोझ बढ़ेगा। यह फंडिंग पैटर्न ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को किसी भी दूसरी केंद्रीय योजना जैसा बना देता है।श टीडीपी चाहती है कि इस विधेयक को संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा जाए। कांग्रेस ने भी यही मांग की है। वहीं सरकार का दावा है कि नया कानून श्विकसित भारत 2047श विजन के अनुरूप है। नॉर्मेटिव फंड्रिंग से बजट में अनिश्चितता खत्म होगी और उद्देश्यपूर्ण पैमानों पर आधारित योजनाबद्ध आबंटन सुनिश्चित होगा। सरकार का विकसित भारत का दावा कोरी राजनीति है। क्योंकि आज से 25 साल बाद के विकास की बात करने से पहले आज की जरूरत पर ध्यान देना चाहिए। 2047 तक विकसित होने का सपना पूरा तभी होगा, जब आज लोगों के पास रोजगार रहेगा। लेकिन मोदी सरकार पहले तो पकौड़ा तलने और रील बनाने को रोजगार बताती है और जो सौ दिन का रोजगार यूपीए सरकार की बदौलत लोगों को मिला हुआ है, उसे भी खत्म करने की तैयारी है।

साफ हवा में सांस लेने की आजादी अभी दूर

> छुट्टी का दिन होने के बावजूद शनिवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (ए.क्यू.आई.) छलांग लगाते हुए 400 पार पहुंच गया। नतीजतन ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) एक ही दिन में दो बार अपडेट करना पड़ा। हालांकि अब सरकारी आंकड़े बहुत विश्वसनीय नहीं रह गए हैं लेकिन उनके मुताबिक भी दोपहर तक दिल्ली में ए.क्यू.आई. 431 हो गया, जिसके चलते पहले से लागू ग्रैप-2 को ग्रैप-3 में बदलना पड़ा तो शाम होते-होते ए.क्यू.आई. 441 हो गया। नतीजतन गहराते वायु प्रदूषण के मद्देनजर वायु गुणवत्ता आयोग की सब कमेटी ने पूरे दिल्ली-एन.सी.आर. में ग्रैप-4 के तहत प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया। फिर भी रविवार की सुबह ए.क्यू.आई. 500 तक पहुंच गया। देश के दिल दिल्ली में हवा की गुणवत्ता इस साल सबसे खराब मानी जा रही है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए जानलेवा वायु प्रदूषण का यह आलम तब है, जब दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए अपनी पीठ खुद थपथपाती रही है। हाल ही में दावा किया गया कि दीवाली पर पटाखे चले और ऑड-ईवन के तहत कारों-बाजारों पर प्रतिबंध भी नहीं लगाए, फिर भी वायु प्रदूषण पिछले साल के मुकाबले नियंत्रण में रहा। लेकिन दिल्ली वालों को साल में उंगलियों पर गिने जा सकने वाले दिन ही वैसी साफ हवा नसीब हो पाती है, वरना पूरे एन.सी.आर. में लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। दीवाली के आसपास तो ए.क्यू.आई. 900-1000 तक पहुंच जाता है। बेशक दिल्ली-एन.सी.आर. निवासियों के लिए सांसों का यह संकट नया नहीं है।

अर्से बाद हुआ है कि सत्तापक्ष और विपक्ष किसी मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए सहमत हो गए। समाधान तो पता नहीं, पर यह भी संतोष की बात है कि संसद दिल्ली-एन.सी.आर. में सांसों पर गहराते संकट पर चर्चा करेगी। वंदे मातरम और चुनाव सुधार पर राजनीतिक रार के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को शून्यकाल में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाते हुए पेशकश की कि सत्तापक्ष और विपक्ष सदन में चर्चा कर समाधान खोजें, तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी चर्चा के लिए सरकार की सहमति जताई। छुट्टी का दिन होने के बावजूद शनिवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (ए.क्यू.आई.) छलांग लगाते हुए 400 पार पहुंच गया। नतीजतन ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) एक ही दिन में दो बार अपडेट करना पड़ा। हालांकि अब सरकारी आंकड़े बहुत विश्वसनीय नहीं रह गए हैं लेकिन उनके मुताबिक भी दोपहर तक दिल्ली में ए.क्यू.आई. 431 हो गया, जिसके चलते पहले से लागू ग्रैप-2 को ग्रैप-3 में बदलना पड़ा तो शाम होते-होते ए.क्यू.आई. 441 हो गया। नतीजतन गहराते वायु प्रदूषण के मद्देनजर वायु गुणवत्ता आयोग की सब कमेटी ने पूरे दिल्ली-एन.सी.आर. में ग्रैप-4 के तहत प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया। फिर भी रविवार की सुबह ए.क्यू.आई. 500 तक पहुंच गया। देश के दिल दिल्ली में हवा की गुणवत्ता इस साल सबसे खराब मानी जा रही है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए जानलेवा वायु प्रदूषण का यह आलम तब है, जब दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए अपनी पीठ खुद थपथपाती रही है। हाल ही में दावा किया गया कि दीवाली पर पटाखे चले और ऑड-ईवन के तहत कारों-बाजारों पर प्रतिबंध भी नहीं लगाए, फिर भी वायु प्रदूषण पिछले साल के मुकाबले नियंत्रण में रहा। लेकिन दिल्ली वालों को साल में उंगलियों पर गिने जा सकने वाले दिन ही वैसी साफ हवा नसीब हो पाती है, वरना पूरे एन.सी.आर. में लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। दीवाली के आसपास तो ए.क्यू.आई. 900-1000 तक पहुंच जाता है। बेशक दिल्ली-एन.सी.आर. निवासियों के लिए सांसों का यह संकट नया नहीं है। एक दशक से तो वे यह संकट झेल ही रहे हैं, जिसका ठीकरा अक्सर दीवाली पर चलाए जाने वाले पटाखों और पड़ोसी राज्यों में जलाई जाने वाली पराली के सिर फोड़ दिया जाता है। दिल्ली सरकार की पैरवी पर सर्वोच्च न्यायालय ने इसी साल, अर्से बाद दीवाली पर सीमित अवधि के लिए ग्रीन पटाखों की अनुमति दी थी। अगले दिन ए.क्यू.आई. गंभीरतम श्रेणी में पहुंच जाना अवधि की सीमा और ग्रीन पटाखों की व्यावहारिकता, दोनों पर ही सवालिया निशान लगा गया। सैंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमैंट (सी.एस.ई.) का मानना है कि पराली अब मुख्य खलनायक नहीं है। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं और वायु प्रदूषण में स्थानीय कारणों का योगदान 85 प्रतिशत तक है। अक्तूबर-नवम्बर में ज्यादातर दिनों वायु प्रदूषण में पराली का योगदान 5 प्रतिशत के आसपास ही रहा। सी.एस.ई. का अध्ययन यह भी बताता है कि वायु प्रदूषण के लिए मुख्य खलनायक वाहन, उद्योग, बिजली संयंत्र और भवन निर्माण आदि हैं। पूरे देश की तो छोडिघ्ए, राजधानी दिल्ली और एन.सी.आर. में भी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। पिछले एक दशक में भी मैट्रो के विस्तार और गिनती की इलैक्ट्रिक बसों के अलावा सार्वजनिक परिवहन को विश्वसनीय बनाने की दिशा में कुछ खास नहीं किया गया। इसीलिए लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार निजी वाहनों का इस्तेमाल करने को बाध्य होते हैं। फिटनैस अवधि और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र को भी नजरअंदाज कर पुरानी निजी कारों पर प्रतिबंध से लोगों के कामकाज और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय सांस लेने लायक साफ हवा नागरिकों का मौलिक अधिकार बता चुका है लेकिन उसका हनन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का अभी तक इंतजार है। आयुष्मान भारत का नारा देने वाली सरकार वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली-एन.सी.आर. निवासियों की ऊम्र 8-10 साल कम होने की आशंका वाले अध्ययनों से कैसे मुंह चुरा सकती है? पद्म पुरस्कार से सम्मानित 80 से अधिक डॉक्टरों ने दिसम्बर के पहले सप्ताह में देश भर में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके प्रदूषण को हैल्थ एमरजैंसी करार दिया था। विडंबना यह है कि उस दिशा में, चिंता जताने से आगे, कोई पहल भी नजर नहीं आती। साल-दर-साल निराशा के बावजूद उम्मीद की जानी चाहिए कि संसद इस मुद्दे पर दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर चर्चा करेगी और कुछ ठोस परिणामपरक दीर्घकालीन रणनीतिक उपायों पर सहमत भी होगी।

नाम बदलने की मुहिम में कहीं काम अधूरा न रह जाए

नाम बदलने की राजनीति दुनिया भर में आम है। मुल्कों, शहरों, सड़कों, इमारतों के नाम बदले जाते हैं। भारत में भी यह प्रक्रिया उत्साह से चलाई गई। एक दौर में जो नाम बदले गए, उनका तर्क स्थानीय परम्परा और पहचान को लौटा लाने का था। इस तर्क से बॉम्बे को मुम्बई किया गया, मद्रास को चेन्नई और कलकत्ता को कोलकाता। ब्रिटिश शासन के समय अंग्रेज शासकों के नाम पर रखे गए नाम भी बदले गए। कर्जन रोड कस्तूरबा गांधी मार्ग हो गया और कनॉट प्लेस राजीव गांधी चौक। हालांकि मुंह पर चढ़े पुराने नाम आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। कनॉट प्लेस भी बना हुआ है। वैसे बीते दिनों नाम बदलने की जो मुहिम चली है, उसका वास्ता मजहबी पहचान और साम्प्रदायिक राजनीति के आग्रह से दिखता है। खासकर मुस्लिम पहचानों की स्टीरियोटाइपिंग की भी कोशिश दिख रही है। दिल्ली में सबसे लंबे समय तक राज करने वाले बादशाह औरंगजेब के नाम पर चलती आ रही सड़क का नाम एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग कर दिया गया- यह कहते हुए कि हमें औरंगजेब जैसे नहीं, कलाम जैसे मुसलमान चाहिए। इलाहाबाद को फिर भी प्रयागराज के रूप में कभी जाना जाता था, लेकिन बहुत लोकप्रिय नामों को बहुत अनजान और संस्कृतनिष्ठ नामों से बेदखल किया जा रहा है। इस वजह से हमारे शहर हमारे ही स्मृति-कोश से बाहर होते जा रहे हैं। नाम बदलने की मुहिम में एक नया उत्साह दिख रहा है। पहले कहा गया कि मनरेगा यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का नाम पूज्य बापू रोजगार गारंटी योजना किया जाएगा। लेकिन फिर खबर आई कि इसकी जगह एक नया नाम चुना गया है- विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)। हिंदी-अंग्रेजी मिले ऐसे अजीब-से नाम की क्या जरूरत थी? क्योंकि इसका संक्षिप्त रूप वीबी-जी राम जी बनता है। क्या यह महात्मा गांधी को पहले पूज्य बापू और फिर राम जी से विस्थापित करने की कोशिश है? इसके पीछे छुपी मंशा समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन नाम बदलने की इस राजनीति में मूल मुद्दे और असुविधाजनक सवाल पीछे रह गए हैं। इस नए कानून में रोजगार गारंटी सौ दिन की नहीं, सवा सौ दिन की होगी। इससे संदेश जाता है कि सरकार ने मजदूरों का, दिहाड़ी पर काम करने वाले लोगों का बहुत खयाल रखा। लेकिन हकीकत क्या है? शनिवार को छपी खबर के मुताबिक केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में जानकारी दी कि मनरेगा के तहत बीते पांच वर्षों में प्रतिवर्ष औसतन 50.24 दिन का रोजगार मिला है। यानी फिलहाल 100 दिन की गारंटी भी पूरी नहीं की जा रही है, फिर इसे 125 दिन कर देने के दिखावे का क्या मतलब है? सरकार रोजगार दे नहीं पा रही या लोग लेने नहीं आ रहे? दोनों ही सूरतों में 125 दिन की गारंटी का दिखावा तार-तार हो जाता है। समस्या बस इतनी नहीं है। सरकार का कहना है कि इस योजना पर अमल राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, केंद्र का काम बस इसकी समीक्षा करना है। लेकिन राज्यसभा में सरकार यह जानकारी भी दे रही है कि इस 5 दिसंबर तक मनरेगा के मद के 9746 करोड़ से ज्यादा की रकम बकाया है। यह 2025-26 के मनरेगा के बजट का करीब 27 फीसदी है। तो सच्चाई यह है कि बीते करीब दो दशकों में जिस योजना ने इस देश के गरीब मजदूरों का पलायन कुछ घटाया, उद्योग-धंधों में चलने वाला उनका शोषण कुछ कम किया, उसे ठीक से लागू तक नहीं किया जा रहा है। नाम महात्मा गांधी रखिए, पूज्य बापू या जय राम जी- योजना अमल में आएगी तो लोगों का भला होगा, वरना आखिरी आदमी तक पहुंचने का जो जंतर गांधी ने दिया था, वही नाकाम हो जाएगा और रामराज्य भी अधूरा रह जाएगा।

वीआईपी दर्शन पर सुप्रीम आदेश, निर्णय केंद्र करे

ये एक जगह नही है, श्रद्धालु को इस समस्या से अधिकांश जगह रूबरू होना पड़ता है। जगहझ्जगह मंदिरों में इस समस्या का सामना होता है। लगभग 40 साल पहले हम कोलकत्ता गए। कालिका जी मंदिर में हम श्रद्धालुओं की लाइन में लगे थे कि हमारे एक साथी ने देखा और हमें इशारा कर अपने पास बुला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में 'वीआईपी दर्शन' सुविधा को चुनौती देने वाली याचिका भले ही खारिज कर दी, किंतु इस याचिका पर कोर्ट द्वारा कही गई बातों की गूंज दूर तक जाएगी। यह गूंज केंद्र सरकार को विवश करेगी कि वह मंदिरों में होने वाले वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगाने वाला निर्णय लें। कोर्ट की ये गूंज आने वाले समय में मंदिरों के वीवीआईपी दर्शन कर रोक लगाने का रास्ता प्रशस्त करेगी। पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह एक नीतिगत मामला है। इस पर केंद्र सरकार को विचार करना होगा। बेंच ने यह भी कहा कि वीआईपी के लिए ऐसा विशेष व्यवहार मनमाना है। यह याचिका मंदिरों की तरफ से वसूले जाने वाले वीआईपी दर्शन शुल्क को समाप्त करने की मांग कर रही थी। पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बेंच इस मुद्दे से सहमत है, लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत निर्देश जारी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, 'हालांकि हमारी राय है कि मंदिरों में प्रवेश के संबंध में कोई विशेष व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हमें नहीं लगता कि यह अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का उपयुक्त मामला है।' यह आदेश में दर्ज किया गया लेकिन मामला सरकार के विचार के लिए छोड़ दिया गया। पूर्व उखकखन्ना ने कहा कि यह मामला कानून-व्यवस्था का प्रतीत होता है और याचिका इस पहलू पर होनी चाहिए थी। बेंच ने कहा, 'हम स्पष्ट करते हैं कि याचिका खारिज होने से संबंधित अधिकारियों को जरूरत के हिसाब से कार्रवाई करने से नहीं रोका जाएगा। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, 'आज 12 ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। ये मनमाना और भेदभाव वाला है। यहां तक कि गृह मंत्रालय ने भी आंध्र प्रदेश से इसकी समीक्षा करने को कहा है। चूंकि, भारत में 60 प्रतिशत पर्यटन धार्मिक है, इसलिए ये भगदड़ की प्रमुख वजह भी है।' सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका विजय किशोर गोस्वामी ने डाली थी। उन्होंने मंदिरों में अतिरिक्त शुल्क लेकर 'वीआईपी दर्शन' के चलन को आर्टिकल 14 के तहत समानता के अधिकार और आर्टिकल 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बताया। उन्होंने दलील दी कि जो लोग इस तरह का शुल्क अदा करने में असमर्थ हैं, ये उनके खिलाफ भेदभाव है। याचिका में जोर देकर कहा गया था कि कई मंदिर 400 से 500 रुपये में लोगों के लिए विशेष दर्शन की व्यवस्था करते हैं। इससे आम श्रद्धालु और खासकर महिलाएं, स्पेशली एबल्ड लोग और सीनियर सिटिजंस को दर्शन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह मामला देश भर के मंदिरों में आम लोगों और वीआईपी के बीच भेदभाव के मुद्दे को उठाता है। वीआईपी दर्शन की सुविधा से आम लोगों को लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता है, जबकि वीआईपी आसानी से दर्शन कर लेते हैं। ये एक जगह नही है, श्रद्धालु को इस समस्या से अधिकांश जगह रूबरू होना पड़ता है। जगहझ्जगह मंदिरों में इस समस्या का सामना होता है। लगभग 40 साल पहले हम कोलकाता गए। कालिका जी मंदिर में हम श्रद्धालुओं की लाइन में लगे थे कि हमारे एक साथी ने देखा और हमें इशारा कर अपने पास बुला लिया। यहां पुजारी पांच रूपया प्रति व्यक्ति लेकर सीधे दर्शन करा रहे थे। अभी वेट द्वारिका जाना हुआ। हम परिवार के छह सदस्य थे। एक पंडित जी ने हमसे पांच सौ रुपए लिए। अलग लाइन से हमें आराम से दर्शन कराए। भीड़-भाड़ भी बची। वैसे दर्शन में दो से तीन घंटे लगते पांच सौ रुपए में आधा घंटा में दर्शन कर मंदिर से बाहर आ गए। करीब दस साल पहले हम गुजरात में अम्बा जी गए थे। दर्शन की लाइन में लगे थे कि कर्मचारियों ने यह कह कर हमके रोक दिया कि दर्शन का समय समाप्त हो गया, जबकि कुछ अन्य को लगातार प्रदेश दिया जा रहा। किसी तरह हम अन्यों वाली पंक्ति में शामिल हुए। तब दर्शन हुए। दर्शन भी बड़े आराम से हुए। काफी समय हम मंदिर में रूके, जबकि ऐसा पहले संभव नही था। इस तरह का भेदभाव हमें कई जगह देखने को मिला। उज्जैन में तो आप पंडित को पांच सौ के आसपास रुपए दीजिए। वह मंदिर के गर्भ गृह में ले जाकर पूजन अर्चन कराते हैं। जो ये रकम नही देते वे गर्भगृह के बाहर ही दूर से दर्शन कर तृप्त हो जाते हैं।

बिग बॉस 19 जीतने के बाद गौरव खन्ना को लगा तगड़ा झटका, लॉन्च के 24 घंटे के भीतर ही यूट्यूब चौनल गायब!

रिएलिटी शो बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना के लिए जीत की खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। शो जीतने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपना यूट्यूब चौनल लॉन्च किया था, लेकिन महज 24 घंटे के भीतर ही उन्हें तगड़ा झटका मिल गया। गौरव का पहला वीडियो अचानक प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया और सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज हो गई कि उनका पूरा चौनल ही टर्मिनेट कर दिया गया है। गौरव खन्ना ने खुद इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर अपने यूट्यूब चौनल की शुरूआत की जानकारी दी थी। इस वीडियो में उन्होंने बताया था कि चौनल लॉन्च करने का पूरा श्रेय उनके करीबी दोस्त मृदुल तिवारी और प्रणित मोरे को जाता है। गौरव ने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा था कि अगर उन्हें किसी टेक्निकल चीज की समझ नहीं आएगी तो वे सीधे इन्हीं दोनों को फोन करेंगे। अपने यूट्यूब वीडियो में गौरव ने बिग बॉस 19 को लेकर भी खुलकर बात की थी।

मूवी डेट पर निकलीं 'लापता लेडीज' की फूल? जानिए किस एक्टर के साथ आईं नजर; शुरू हुई डेटिंग की चर्चा

लापता लेडीज फेम अभिनेत्री नितांशी गोयल इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चचाओं में हैं। उनका नाम उनके को-एक्टर संग जोड़ा जा रहा है क्योंकि अक्सर दोनों एक दूसरे के साथ नजर आते हैं। अब ऐसा ही हाल ही में भी देखने को मिला। अभिनेत्री नितांशी गोयल इन दिनों प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल जिंदगी को लेकर भी सुर्खियों में हैं। नितांशी हाल ही में को-स्टार अभय वर्मा के साथ फिल्म देखने पहुंचीं, जिसकी तस्वीर उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पर साझा की। अभय को 'मुंज्या' फिल्म के अलावा 'द फैमिली मैन 2' सीरीज से भी काफी पहचान मिली। इसके अलावा एक्टर के पास कई आगामी प्रोजेक्टर भी मौजूद हैं। पिछले काफी समय से अभय के नितांशी गोयल के साथ नजदीकियों के चर्चे हैं। अब गॉसिप गलियारों की मानें तो दोनों को अक्सर साथ देखा जाता है जिससे ये अफवाहें तूल पकड़ती जा रही हैं। मूवी देखने निकले नितांशी और अभय नितांशी ने इंस्टाग्राम पर अभय के साथ तस्वीर साझा करते हुए फैंस को जानकारी दी कि वो फिल्म देख रहे हैं। फोटो में नितांशी के हाथ में पॉपकॉर्न नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कैप्शन में लिखा है- 'मैं पहली बार देख रही हूं और वो तीसरी बार देख रहा है। अंदाजा लगाएं कि कौन कहानी को समझा रहा है।' इसके साथ ही नितांशी ने आंखों और पॉपकॉर्न का इमोजी भी लगाया है जिससे पता चल रहा है कि यहां वो फिल्म देखने की बात कर रही हैं। नितांशी ने अभय को दी थी जन्मदिन की बधाई इसी साल जुलाई में अभिनेत्री नितांशी गोयल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की थी। इसमें उन्होंने अभिनेता अभय वर्मा का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें एक्टर को केक काटते हुए देखा जा सकता था। इसके साथ नितांशी गोयल ने कैप्शन में लिखा था, अभय वर्मा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। साथ ही आप बहुत दयालु और शांत होने के साथ एक खास इंसान भी हैं। ये साल आपको ढेर सारी खुशियां और प्यार दें, जिसके आप हकदार हैं।

शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा की 60 करोड़ के ठगी मामले में बढ़ी मुश्किलें, बिजनेसमैन ने आरोपों को झुठलाया

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने 60 करोड़ से धोखाधड़ी मामले में पहली बार आधिकारिक बयान जारी किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस केस में चुप्पी तोड़ी है।

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति-बिजनेसमैन राज कुंद्रा एक बार फिर कानूनी विवादों को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार मामला 60 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी और ठगी से जुड़ा है, जिसकी जांच आर्थिक अपराध शाखा कर रही है। इस पूरे प्रकरण पर अब राज कुंद्रा ने सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया दी है और खुद पर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। राज-शिल्पा की बढ़ीं मुश्किलें मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेज विंग ने 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी मामले में कपल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) जोड़ दी है। यह कार्रवाई जांच के दौरान सामने आए नए सबूतों के आधार पर की गई है। राज कुंद्रा ने दिया आधिकारिक बयान राज कुंद्रा ने अपने आधिकारिक बयान में साफ शब्दों में कहा है कि उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ लगाए जा रहे आरोप न सिर्फ तथ्यहीन हैं, बल्कि इन्हें जानबूझकर आपराधिक रंग दिया जा रहा है। उनका कहना है कि यह मामला पहले से ही अदालत के विचाराधीन है और उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है, जिस पर सुनवाई चल रही है। बिजनेसमैन ने ये भी साफ किया कि उन्होंने जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग किया है और भविष्य में भी करते रहेंगे। उनके मुताबिक, उन्हें भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और उन्हें विश्वास है कि सच सामने आएगा।

धर्मेंद्र की याद में दोबारा रिलीज होगी यमला पगला दीवाना, मेकर्स बोले- इसकी री-रिलीज सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं..

दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र भले ही अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके चाहने वाले आए दिन उन्हें किसी न किसी बहाने याद करते नजर आते हैं। वहीं, हाल ही में एनएच स्टूडियोज के मालिक श्रेयांश हिरावत ने धर्मेंद्र की यादों को सहेजते हुए उनकी सुपरहिट फिल्म यमला पगला दीवाना को सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज का फैसला लिया है। फिल्म के अधिकार रखने वाली कंपनी एनएच स्टूडियोज के मालिक श्रेयांश हिरावत ने यमला पगला दीवाना की री-रिलीज को लेकर कहा- शुरूआत में हमारी योजना यह थी कि हम इस फिल्म को दिसंबर में धर्मेंद्र के जन्मदिन के आस-पास दोबारा रिलीज करेंगे। लेकिन धरम जी के निधन के बाद जो भावनात्मक माहौल बना, उसे देखते हुए हमें लगा कि थोड़ा रुकना बेहतर होगा। यह सिर्फ एक कमर्शियल फैसला नहीं था, बल्कि पूरी तरह भावनाओं से जुड़ा मामला था। हम चाहते थे कि जो भी कदम उठाया जाए, वह पूरे सम्मान और सही समय के साथ हो इसलिए हमने तय किया कि रिलीज को थोड़े समय के लिए आगे बढ़ाया जाए। हां, इतना तो तय है कि फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में लौटेगी। फिल्म से जुड़ी यादें शेयर करते हुए श्रेयांश ने कहा, यह फिल्म हमारे लिए इसलिए भी बेहद खास है, क्योंकि यमला पगला दीवाना हमने सीधे धर्मेंद्र जी से खरीदी थी। मुझे आज भी याद है, मुंबई में सनी सुपर साउंड के ऑफिस में जाकर हमने इस फिल्म के पेपर्स साइन किए थे। बात साल 2012 की है। उस समय मैं अपने करियर के शुरूआती दौर में था और बिजनेस सीख रहा था। धर्मेंद्र जी, सनी देओल सर, सभी वहां मौजूद थे और उन्हीं के हाथों से हमने यह फिल्म ली थी। उस वक्त उनकी बातचीत, उनका भरोसा और उनका अपनापन, वही इस फिल्म को हमारे लिए हमेशा यादगार बनाए रखेगा।श्रेयांश ने यह भी कहा कि यमला पगला दीवाना देओल परिवार के लिए सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी। वो कहते हैं, यह फिल्म देओल परिवार के लिए बहुत अहम रही। इससे पहले भी उन्होंने अपने-अपने स्तर पर काम किया था, लेकिन यह फिल्म एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी। धर्मेंद्र जी, सनी और बॉबी देओल को एक साथ इस तरह देखना दर्शकों को बेहद पसंद आया। यह फ्रेंचाइजी उनके अपने घर से निकली और सीधे ब्लॉकबस्टर साबित हुई।

कैटरीना-विक्की से लेकर कियारा-सिद्धार्थ तक..2025 में इन कपल्स को मिला पेरेंट्स बनने का सुख, पहली बार आंगन में गूंजी किलकारी

साल 2025 महज कुछ दिनों में खत्म होने को है और यह वर्ष लोगों को कई खट्टी-मीठी यादें देकर जा रहा है। वहीं, बॉलीवुड सितारों के लिए ये साल बेहद खास और यादगार साबित हुआ। इस साल कई फेमस कपल्स के घर बच्चे के किलकारियां गूंजी, जिससे उनकी सुनी गोद भर गई और आंगन चहक उठा। तो आइए जानते हैं उन बॉलीवुड कपल्स के बारे में, जो साल 2025 में माता-पिता बने। बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय कपल्स में शामिल विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने शादी के बाद इस साल अपने पहले बच्चे का स्वागत किया। कैटरीना ने नवंबर 2025 में पति विक्की के बेटे को जन्म दिया। हालांकि, कपल ने अब तक न तो अपने बेटे की झलक सार्वजनिक की है और न ही उसका नाम रिवील किया है। बेहतरीन अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले राजकुमार राव और उनकी पत्नी पत्रलेखा भी इस साल माता-पिता बने। नवंबर 2025 में पत्रलेखा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। इस खुशी को कपल ने बेहद सादगी के साथ सेलिब्रेट किया। फैंस के चहेते कपल्स में से एक सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने भी इस साल अपने पहले बच्चे का स्वागत किया। उनके घर जुलाई 2025 में नन्ही परी का आगमन हुआ। कपल ने अपनी बेटी का नाम सारायाह मल्होत्रा रखा है। हालांकि, अब तक उन्होंने अपनी बेटी का चेहरा नहीं दिखाया है और उसकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रख रहे हैं। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राजनेता राघव चड्ढा भी इस साल माता-पिता बने। परिणीति ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ शेयर की। पोस्ट में उन्होंने भावुक शब्दों में लिखा कि अब उनका परिवार पूरा हो गया है। एक्टर और प्रोड्यूसर अरबाज खान और उनकी पत्नी शूरा के घर अक्टूबर 2025 में खुशियों ने दस्तक दी। शूरा ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम कपल ने सिपारा रखा है। बेटी के जन्म के बाद से दोनों बेहद खुश नजर आ रहे हैं और इस नए सफर को एंजॉय कर रहे हैं। क्रिकेटर केएल राहुल और एक्ट्रेस अथिया शेट्टी भी 2025 में पेरेंट्स बने। फरवरी में अथिया ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम इवारा रखा गया है। इस खुशी के साथ एक्टर सुनील शेट्टी नाना भी बन गए, जिसे लेकर उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की। कुल मिलाकर साल 2025 बॉलीवुड सितारों के लिए सिर्फ करियर ही नहीं, बल्कि पर्सनल लाइफ के लिहाज से भी बेहद खास रहा। इन कपल्स के घर आए नन्हे मेहमानों ने फैंस को भी खुशियों से भर दिया और सोशल मीडिया पर बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी रहा।

कलरफुल ड्रेस में मृणाल ठाकुर ने किया रैंप वॉक, अदाओं से जीता फैंस का दिल

अभिनेत्री मृणाल ठाकुर ने हाल ही में एक फैशन इवेंट में हिस्सा लिया है। उन्होंने शानदार ड्रेस में रैंप वॉक की है। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल है। अभिनेत्री मृणाल ठाकुर अपनी बेहतरीन अदाकारी के साथ अपने जबरदस्त लुक और स्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं। हाल ही में वह एक फैशन इवेंट में नजर आईं। यहां उन्होंने खूबसूरत ड्रेस में रैंप वॉक किया। अभिनेत्री के लुक की काफी तारीफ हो रही है। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आइए डालते हैं एक नजर। वायरल हो रहा मृणाल ठाकुल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि मृणाल ठाकुर ने कलरफुल ऑफ शोल्डर ड्रेस में गौरी एंड नैनिका के लिए रैंप वॉक किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रैंप वॉक करते हुए मृणाल ठाकुर काफी खुश हैं। वह चेहरे से शानदार एक्सप्रेशन दे रही हैं। मृणाल ठाकुर का वर्कफ्रंट मृणाल ठाकुर हिंदी के अलावा मराठी और तेलुगु फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। वह आखिरी बार बॉलीवुड फिल्म 'सन ऑफ सरदार' में नजर आई थीं। जल्द ही वह फिल्म 'दो दीवाने सहर में', 'है जवानी तो इश्क होना है' और 'पूजा मेरी जान' का हिस्सा होंगी।

नेहा कक्कड़ के कैंडी शॉप को सुनकर नेटिजेंस ने पकड़ा माथा, ढिंचैक पूजा से कर डाली तुलना; बोले- अब तो रुक जाओ

नेहा कक्कड़ इन दिनों अपने नए गाने ह्यकैंडी शॉप को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। उनका ये गाना रिलीज होते ही नेटिजेंस के निशाने पर आ गया है। जानिए गाने को सुनने के बाद लोगों ने दिए कैसे रिएक्शन सिंगर नेहा कक्कड़ का नया गाना ह्यकैंडी शॉप इन दिनों चचाओं में बना है। अपने नाम से ही ये गाना लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। अब गाना रिलीज होने के बाद नेहा कक्कड़ लोगों के निशाने पर आ गई हैं। सोशल मीडिया पर नेटिजेंस गाने के बोल और नेहा कक्कड़ के डांस दोनों की जमकर आलोचना कर रहे हैं। एक ओर जहां कई यूजर्स गाने के लिरिक्स को लेकर हैरानी जता रहे हैं, तो वहीं कई लोगों का कहना है कि अब तो नेहा कक्कड़ ने हद ही पार कर दी है। जानिए इस गाने के रिलीज होने के बाद नेटिजेंस ने कैसे-कैसे रिएक्शन दिए हैं यूजर्स के निशाने पर आया नेहा कक्कड़ का गाना टोनी कक्कड़ और नेहा कक्कड़ अपना नया गाना ह्यकैंडी शॉप लेकर आए हैं। लेकिन गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार हो गया। लोगों ने नेहा कक्कड़ के इस गाने और उनके डांस को अश्लील बता दिया। वहीं कई लोगों ने गाने के लिरिक्स को लेकर नेहा को जमकर ट्रोल कर दिया। जबकि कई नेटिजेंस ने इस गाने को सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। एक यूजर ने इस गाने को लेकर लिखा कि यह सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया गया है। एक अन्य ने लिखा कि नेहा कक्कड़ का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। लोगों ने की गाना डिलीट करने की विनती एक यूजर ने लिखा कि बचपन में लोगों से सुनते थे कि गाने उनके जमाने में अच्छे बनते हैं, अब लगता है कि वो सच कहते थे। एक यूजर ने गाने को डिलीट करने का अनुरोध किया। तो वहीं एक ने कहा कि अब तो भगवान ने भी हाथ जोड़ लिए हैं। अब तो रुक जाओ।

हर मौसम में दमकती त्वचा का राज, घर पर करें ये 5 असरदार नुस्खे, निखर उठेगा चेहरा

अगर आप हर मौसम में हेल्दी और दमकती स्किन पाना चाहती हैं, तो आपको घर पर ही कुछ सिंपल लेकिन असरदार नेचुरल रूटीन अपना सकती हैं। यह न सिर्फ आपकी त्वचा को निखारने का काम करेंगे, बल्कि आपकी स्किन को लंबे समय तक जवां भी बनाएं रखेंगे।

हर मौसम में स्किन की देखभाल करना बेहद जरूरी है। क्योंकि बदलते मौसम में त्वचा की जरूरतें भी बदल जाती हैं। कई बार गर्मियों में स्किन ऑयली हो जाती है, तो वहीं सर्दियों में स्किन रूखी और बेजान हो जाती है। अगर आप हर मौसम में हेल्दी और दमकती स्किन पाना चाहती हैं, तो आपको घर पर ही कुछ सिंपल लेकिन असरदार नेचुरल रूटीन अपना सकती हैं।

यह न सिर्फ आपकी त्वचा को निखारने का काम करेंगे, बल्कि आपकी स्किन को लंबे समय तक जवां भी बनाएं रखेंगे। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको नेचुरल स्किन केयर रूटीन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हर मौसम में आपकी त्वचा का ख्याल रखेंगे।

ड्रग्स लेते थे मस्क, हर घटना के पीछे साजिश देखते हैं वेंस

वॉशिंगटन डीसी। व्हाइट हाउस की वरिष्ठ अधिकारी सूसी वाइल्स ने दावा किया है कि दिग्गज कारोबारी एलन मस्क केटोमाइन का सेवन करते थे। उन्होंने यह भी कहा कि उप राष्ट्रपति जेडी वेंस बिना पक्के सबूतों के हर घटना के पीछे गोपनीय साजिश मानने वाले व्यक्ति हैं। व्हाइट हाउस की वरिष्ठ अधिकारी सूसी वाइल्स ने एक पत्रिका को दिए इंटरव्यू में चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीब लोगों के बारे में स्पष्ट और आलोचनात्मक टिप्पणियां कीं। उन्होंने यह भी कहा कि टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एलन मस्क केटामाइन (ड्रग) का सेवन करते थे। उन्होंने उप राष्ट्रपति जेडी वेंस को 'बिना सबूतों के हर बड़ी घटना के पीछे गोपनीय साजिश मानने वाला व्यक्ति' और बजट प्रमुख रस वॉट को 'कट्टर दक्षिणपंथी' बताया। उन्होंने जेफरी एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों को संभालने के तरीके को लेकर अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी की भी आलोचना की। इस इंटरव्यू के सामने आने के व्हाइट हाउस ने उनके

बयानों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि, सूसी वाइल्स ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस खबर में जरूरी संदर्भों को नजरअंदाज किया गया और इसे जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया गया। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने सूसी वाइल्स का समर्थन करते हुए कहा कि ट्रंप के पास सूसी से बड़ा या उनसे ज्यादा वफादार सलाहकार कोई नहीं है। लीविट ने एक्स पर कहा, 'पूरा प्रशासन उनके स्थिर नेतृत्व के लिए आभारी है और पूरी तरह उनके साथ खड़ा है।' लेकिन यह इंटरव्यू फिर से राष्ट्रपति और उनकी नीतियों पर सवाल खड़े कर सकता है और पुराने मतभेद, खासकर मस्क के साथ फिर से टकराव पैदा कर सकता है। वाइल्स ने मस्क के बारे में कहा, वह पूरी तरह अकेले काम करने वाले व्यक्ति हैं। एलन के साथ चुनौती यह है कि उनकी गति के साथ कदम मिलाना मुश्किल है। जब उनसे पूछा गया कि मस्क ने एक्स पर जो पोस्ट शेयर की थी, जिसमें कहा गया था कि सरकारी कर्मचारी एडॉल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन और माओ जेदोंग के समय लाखों मौतों के लिए जिम्मेदार थे, इसके बारे में उनका क्या विचार है, तो वाइल्स ने कहा, मुझे लगता है उस समय वह हल्का ड्रग (माइक्रोडोजिंग) का इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि, वाइल्स ने माना कि उन्हें मस्क के ड्रग इस्तेमाल की प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है। मस्क और टेस्ला के प्रतिनिधियों ने इस बारे में तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मस्क ने इस साल पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट को खारिज किया, जिसमें कहा गया था कि वह केटामाइन और अन्य दवाओं का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई साल पहले डॉक्टर की सलाह पर केटामाइन आजमाया था, लेकिन उसके बाद कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। मस्क ने सरकारी दक्षता विभाग का नेतृत्व किया था, जिसका मकसद संघीय सरकार और उसके कर्मचारियों की संख्या कम करना था। उन्होंने शुरूआत में यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट को बंद करने का लक्ष्य रखा। इस कदम ने वॉशिंगटन को चौंका दिया था और कई मानवीय कार्यक्रमों के बंद होने का कारण बना था। वाइल्स ने कहा कि जब मस्क ने ऐसे कार्यक्रम बंद किए जिन्हें ट्रंप बचाना चाहते थे, तो वह 'शुरूआत में हैरान' रह गईं और उन्होंने मस्क का सामना किया। वाइल्स ने बताया, एलन का रवैया है कि काम जल्दी करना जरूरी है। ऐसे रवैये में कुछ नुकसान तो होगा। लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति यह नहीं सोच सकता कि यूएसएआईडी की प्रक्रिया अच्छी थी। बिल्कुल कोई नहीं। वाइल्स व्हाइट हाउस में चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर हैं और उन्होंने यह इंटरव्यू वैनिटी फेयर पत्रिका को दिया है।

संदिग्ध बंदूकधारी पर हत्या के 15 मामले दर्ज सिडनी पुलिस ने 59 वारदातों में बनाया आरोपी

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर यहूदी समारोह हनुक्का के समारोह के दौरान लोगों पर गोलियां बरसाने वाले संदिग्ध बंदूकधारी पर हत्या के 15 मामले दर्ज किए गए हैं। यह संदिग्ध हमलावर अभी अस्पताल में भर्ती है। उसे कुल 59 वारदातों में आरोपी बनाया गया है। सिडनी के बॉन्डी बीच पर गोलीबारी करने के मामले में संदिग्ध बंदूकधारी पर मंगलवार को पुलिस ने 59 आरोप लगाए, जिनमें 15 हत्या के मामले शामिल हैं। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 24 वर्षीय संदिग्ध बंदूकधारी (नवीद अकरम) तब से सिडनी के अस्पताल में भर्ती है, जब पुलिस ने उसे और उसके पिता (50 वर्षीय) को गोली मारी थी। पुलिस अधिकारी ने बताया, पिता (साजिद अकरम) घटनास्थल पर ही मारा गया। इन आरोपों में मारे गए प्रत्येक पीड़ित के लिए एक-एक हत्या का मामला और एक आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने का मामला भी शामिल है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के अनुसार, इस हमले में 15 लोगों की मौत हुई। मृतकों में एक 10 साल की बच्ची भी शामिल थी। बॉन्डी बीच गोलीबारी के पीछे शामिल दोनों संदिग्ध हमलावरों की पहचान सोमवार सुबह (स्थानीय समय) की गई। पुलिस ने बताया कि 50 वर्षीय और 24 वर्षीय दो पुरुष ही इस हमले में शामिल एकमात्र शूटर थे। इससे पहले बीबीसी और एएफपी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के हवाले से कहा कि यह हमला आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) की विचारधारा से प्रेरित था। हमलावरों की कार से इस्लामिक स्टेट का झंडा और कुछ विस्फोटक बरामद होने के बाद जांच एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है।

कतर ने नौसेना के पूर्व अधिकारी पुर्णेंदु तिवारी को जेल भेजा

दोहा। कतर में नौसेना के पूर्व कमांडर पुर्णेंदु तिवारी को एक बार फिर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जिसके बाद उनके परिवार ने पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मदद की गुहार लगाई है। तिवारी 2022 में गिरफ्तार किए गए भारतीय नौसैना के आठ पूर्व अधिकारियों में शामिल थे, जिनमें से सात को माफी मिलने के बाद भारत लौटने की अनुमति मिली थी। कतर के अधिकारियों ने नौसेना के पूर्व कमांडर पुर्णेंदु तिवारी को एक बार फिर गिरफ्तार किया है। उनके परिवार ने दावा किया कि इस महीने की शुरूआत में उन्हें हिरासत में लिया गया है और छह दिसंबर को जेल भेज दिया गया। अब उनके परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री

एस जयशंकर से दखल कर उनकी रिहाई सुनिश्चित कराने की अपील की है। पुर्णेंदु तिवारी भारतीय नौसेना के उन आठ पूर्व अधिकारियों में शामिल थे, जिन्हें 16 अगस्त 2022 को कतर में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। कूटनीतिक प्रयासों के बाद कतर सरकार ने उनमें से सात को माफी दे दी थी और वे पिछले साल फरवरी में भारत लौट आए थे। हालांकि, एक अलग कानूनी मामले के चलते पुर्णेंदु तिवारी भारत नहीं लौट सके। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, पुर्णेंदु तिवारी एक अलग वित्तीय जांच का सामना कर रहे थे। पीएम मोदी ने कतर के अमीर के सामने उठाया था मामला इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी के साथ भारत यात्रा के दौरान यह मामला उठाया था। उन्होंने कतर में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता की भी सराहना की थी और दोनों देशों के बीच मजबूत कूटनीतिक संबंधों का जिक्र किया था। फिलहाल तिवारी जेल में हैं और पिछले कुछ दिनों में वह अपने परिवार से केवल दो बार ही बात कर पाए हैं।

ट्रंप ने पांच और देशों पर लगाया यात्रा प्रतिबंध इनके नागरिकों के अमेरिका में घुसने पर लगी रोक

वॉशिंगटन। ट्रंप प्रशासन ने यात्रा प्रतिबंध का दायरा बढ़ाते हुए पांच और देशों को इसमें शामिल कर दिया है। वहीं आंशिक पाबंदियों वाले देशों

की सूची में भी 15 और देशों के नाम जोड़े गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अपने यात्रा प्रतिबंध के दायरे का विस्तार किया है और पांच और देशों को इसमें शामिल किया है। साथ ही कई देशों पर नई पाबंदियां भी लगाई हैं। मंगलवार को ट्रंप प्रशासन द्वारा जारी आदेश, उसकी अप्रवासन नीति को और सख्त करने की लगातार कोशिशों का हिस्सा है। साथ ही यह फैसला ऐसे समय लिया गया है, जब बीते दिनों अफगानिस्तान मूल के एक व्यक्ति ने वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड्स के दो सैनिकों को गोली मार दी थी। जून में 12 देशों के नागरिकों पर लगाया था प्रतिबंध इससे पहले जून में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देशों के नागरिकों पर अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगाया था और सात अन्य देशों के लोगों पर कई पाबंदियां लगाई थीं। अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी ट्रंप ने इस तरह की नीति अपनाई थी। जिन 12 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया गया था, उनमें अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, रिपब्लिक ऑफ कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल थे और बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला के नागरिकों पर कड़ी पाबंदियां लगाई गई थीं। अब इन पांच देशों पर भी लगाया यात्रा प्रतिबंध मंगलवार को, ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की कि वह उन देशों की सूची बढ़ा रहे हैं, जिनके नागरिकों के अमेरिका में आने पर प्रतिबंध है। इस सूची में बुर्किना फासो, माली, नाइजर, साउथ सूडान और सीरिया को शामिल किया गया है। सरकार ने फलस्तीनी अथॉरिटी द्वारा जारी यात्रा दस्तावेजों वाले लोगों के भी अमेरिका यात्रा पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। वहीं आंशिक पाबंदियों का सामना कर रहे देशों की सूची में अब 15 और देशों को भी जोड़ा गया है। इनमें अंगोला, एंटीगुआ और बारबुडा, बेनिन, कोटे डी आइवर, डोमिनिका, गैबॉन, गैम्बिया, मलावी, मॉरिटानिया, नाइजीरिया, सेनेगल, तंजानिया, टोंगा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे शामिल हैं।

नेतन्याहू से मिले एस जयशंकर भारत और इस्त्राइल की साझेदारी को नई ऊंचाई देने पर जोर

तेल अवीव। विदेश मंत्री एस. जयशंकर इस्त्राइल दौरे पर हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात कर तकनीक, अर्थव्यवस्था, कौशल और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इस दौरान जयशंकर ने कहा कि भारत-इस्त्राइल की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। नेतन्याहू ने भी इस सहयोग को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों इस्त्राइल के दौरे पर हैं। उनका ये दौरा भारत और इस्त्राइल के रिश्तों को और मजबूती देने की दिशा में बड़ा कूटनीतिक कदम माना जा रहा है। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को इस्त्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। जयशंकर ने कहा कि भारत और इस्त्राइल की रणनीतिक साझेदारी आगे और मजबूत होगी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि उन्होंने नेतन्याहू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं भी दीं है। जयशंकर और नेतन्याहू ने तकनीक, आर्थिक क्षेत्र, कौशल और प्रतिभा, कनेक्टिविटी और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। नेतन्याहू ने भी जयशंकर से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में काम जारी रहेगा। निर बरकास से की मुलाकात पीएम के बाद विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को यरूशलम में इस्त्राइल के अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्री निर बरकात से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच निवेश, नवाचार और व्यापारिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। जयशंकर ने भरोसा जताया कि भारत-इस्त्राइल मुक्त व्यापार समझौता जल्द पूरा होगा, जिससे आर्थिक साझेदारी को नई गति मिलेगी। दो दिन के इस्त्राइल दौरे पर पहुंचे जयशंकर ने देश के शीर्ष नेतृत्व से भी बातचीत की। उन्होंने इस्त्राइल के विदेश मंत्री गिडियन साअर, राष्ट्रपति इसहाक हरजोग और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। यह यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू के प्रस्तावित भारत दौरे की तैयारियां चल रही हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, जिसके बाद इस्त्राइली प्रधानमंत्री ने जल्द मुलाकात का संकेत दिया था। एफटीए से निवेश और नवाचार को बढ़ावा जयशंकर ने निर बरकात के साथ बैठक के बाद कहा कि दोनों देशों ने निवेश और नवाचार सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि भारत-इस्त्राइल मुक्त व्यापार समझौता जल्द पूरा होने से आर्थिक साझेदारी को बड़ा लाभ मिलेगा। दोनों देश तकनीक, स्टार्टअप, उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में एक-दूसरे के पूरक हैं और इसका लाभ उठाने की जरूरत है। आतंकवाद पर भारत-इस्त्राइल की सख्त नीति जयशंकर ने सिडनी के बॉन्डी बीच पर हनुक्का समारोह के दौरान हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि भारत और इस्त्राइल दोनों ही आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं। जयशंकर ने इस्त्राइल को भारत के आतंकवाद विरोधी संघर्ष में लगातार समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के हर रूप और स्वरूप के खिलाफ दोनों देश एकजुट हैं। रणनीतिक साझेदारी और क्षेत्रीय शांति विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत-इस्त्राइल रणनीतिक साझेदारी काफी मजबूत हुई है। इसमें सरकार से सरकार, कारोबार से कारोबार और लोगों से लोगों के बीच संपर्क शामिल है। जयशंकर ने गाजा शांति योजना के प्रति भारत के समर्थन को दोहराया और उम्मीद जताई कि इससे क्षेत्र में स्थायी और टिकाऊ

ईयू उत्सर्जन लक्ष्यों को कर रहा कमजोर यूरोप के रुख से दबाव में ब्रिटेन के ईवी लक्ष्य

नई दिल्ली। यूरोपीय यूनियन द्वारा अगले दशक के मध्य तक टेलपाइप उत्सर्जन को खत्म करने की अपनी योजना को हल्का करने का प्रस्ताव देने के बाद, यूके महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक-वाहन लक्ष्यों के मामले में पीछे हट रहा है। यूरोपीय संघ द्वारा उत्सर्जन मानकों को नरम करने के संकेत मिलने के बाद ब्रिटेन के इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) लक्ष्यों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। यूरोप जहां टेलपाइप उत्सर्जन को पूरी तरह खत्म करने की समयसीमा पर पुनर्विचार कर रहा है, वहीं ब्रिटेन अब भी अपने बेहद महत्वाकांक्षी ईवी रोडमैप पर टिका हुआ है। इस बढ़ते अंतर ने ब्रिटेन को यूरोप से अलग-थलग स्थिति में खड़ा कर दिया है। खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक ऑटोमोबाइल उद्योग निवेश और उत्पादन के अगले चरण को लेकर फैसले ले रहा है। ब्रिटेन का सख्त जीरो-एमिशन रोडमैप ब्रिटेन की जीरो-एमिशन व्हीकल (एंड) नीति के तहत कार निमार्ताओं को हर साल इलेक्ट्रिक कारों और वैन की बिक्री हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। ताकि 2035 तक 100 प्रतिशत बिक्री शून्य-उत्सर्जन वाहनों

की हो सके। एस्टन मार्टिन और जगुआर लैंड रोवर जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड्स वहीं मौजूद है, इसके बावजूद इस लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं माना जा रहा। खासतौर पर तब, जब यूरोपीय संघ खुद अपने सख्त रुख से पीछे हटता दिख रहा है। बर्मिंघम बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर डेविड बेली के अनुसार, किसी भी बड़े ऑटोमोबाइल उद्योग वाले देश ने इतना आक्रामक लक्ष्य तय नहीं किया है। जिससे ब्रिटेन अब नीति के मामले में अलग-थलग नजर आता है। निवेश के फैसलों पर बढ़ती अनिश्चितता नीति में यह अंतर ऐसे समय में सामने आया है, जब वाहन निमार्ता यह तय कर रहे हैं कि अगली पीढ़ी के ईवी प्लांट कहां लगाए जाएं। ब्रिटेन के कारखाने पहले ही ऊंची ऊर्जा लागत, ब्रेक्जिट के बाद व्यापारिक अड़चनों और चीनी निमार्ताओं से बढ़ती प्रतिस्पर्धा से जूझ रहे हैं। चूंकि ब्रिटेन में बनी अधिकांश कारें यूरोप को निर्यात की जाती हैं। ऐसे में यूरोपीय नियमों से अलग रुख अपनाना निवेशकों के लिए अनिश्चितता बढ़ा रहा है। ईवी अपनाने में ब्रिटेन आगे, लेकिन जोखिम बरकरार उपभोक्ता स्तर पर यूरोप के कई देशों की तुलना में ब्रिटेन ने ईवी को तेजी से अपनाया है। अक्तूबर तक के एक साल में ब्रिटेन में नई कार बिक्री का 22 प्रतिशत हिस्सा पूरी तरह इलेक्ट्रिक मॉडल्स का रहा। जो यूरोपीय संघ के औसत 16 प्रतिशत और जर्मनी के 18 प्रतिशत से अधिक है। इसी दौरान चीनी ब्रांड्स जैसे बीवाईडी, जैकू, ओमोडा और लीपमोटर भी ब्रिटेन के बाजार में तेजी से जगह बना रहे हैं। और इस साल बिकने वाली हर 10 में से एक नई कार इन्हीं ब्रांड्स की रही है। यूरोप पर निर्भर ब्रिटिश ऑटो उद्योग स्थानीय बिक्री बढ़ने के बावजूद ब्रिटिश ऑटो उद्योग यूरोप में होने वाले बदलावों से गहराई से जुड़ा हुआ है। उद्योग संगठन एसएमएमटी के अनुसार, ब्रिटेन में बनने वाली लगभग 75 प्रतिशत गाड़ियां निर्यात होती हैं, जिनमें से आधी यूरोपीय संघ जाती हैं। इस सेक्टर से करीब दो लाख लोगों को रोजगार मिलता है। एसएमएमटी के सीईओ माइक हॉजेस का कहना है कि यूरोप ब्रिटेन के लिए सबसे बड़ा निर्यात बाजार और आयात स्रोत है। इसलिए वहां की नीतियां सीधे ब्रिटेन को प्रभावित करती हैं। बार-बार बदली गई समयसीमा ने बढ़ाई उलझन ब्रिटेन की ईवी नीति पिछले कुछ वर्षों में कई बार बदली जा चुकी है। 2017 में तत्कालीन प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने पेट्रोल-डीजल कारों पर 2040 तक प्रतिबंध की घोषणा की थी। बाद में बोरिस जॉनसन ने इसे 2030 कर दिया। जबकि ऋषि सुनक ने उद्योग और उपभोक्ताओं को अधिक समय देने के लिए इसे फिर 2035 तक बढ़ा दिया। मौजूदा सरकार ने 2030 में नई पेट्रोल-डीजल कारों पर प्रतिबंध बहाल करते हुए 2035 तक हाइब्रिड वाहनों की अनुमति दी है। हालांकि, बार-बार के इन बदलावों से कंपनियों की दीर्घकालिक निवेश योजनाएं प्रभावित हुई हैं। यूरोपीय बदलाव से कंपनियों की रणनीति पर असर यूरोपीय संघ के रुख में बदलाव का असर कंपनियों की उत्पादन रणनीति पर भी दिखने लगा है। निसान के यूरोपीय क्षेत्रीय प्रमुख मासिमिलियानो मेसिना ने संकेत दिया है कि कंपनी अब पहले की तुलना में ज्यादा प्लग-इन हाइब्रिड वाहनों का उत्पादन कर सकती है। सुंदरलैंड स्थित निसान प्लांट, जहां सालाना चार लाख कारों की क्षमता है, पहले ही ईवी और बैटरी उत्पादन में भारी निवेश कर चुका है। नीति में ढील की मांग और स्वास्थ्य चिंताएं मेसिना ने ब्रिटेन सरकार से 2028 से प्रस्तावित 'पे-पर-माइल' टैक्स पर भी पुनर्विचार की मांग की है, जो ईवी और प्लग-इन हाइब्रिड मालिकों पर लागू होगा। वहीं, कार्डिफ बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर पीटर वेल्स का मानना है कि यूरोपीय संघ का कदम ब्रिटिश सरकार को लक्ष्य नरम करने का राजनीतिक अवसर दे सकता है।

कनाडाई शिष्टमंडल के वेस्ट बैंक जाने पर रोक, इस्त्राइल का आरोप आतंकी संगठन से संबंध

तेल अवीव। इस्त्राइल ने कनाडा से आए एक निजी प्रतिनिधिमंडल को वेस्ट बैंक में प्रवेश से रोक दिया,

जिसमें छह कनाडाई सांसद शामिल थे। इस्त्राइल का कहना है कि दल के संबंध इस्लामिक रिलीफ वर्ल्डवाइड से हैं, जिसे वह आतंकी संगठन मानता है। कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद ने इस व्यवहार पर आपत्ति जताई। इस्त्राइल ने मंगलवार को कनाडा से आए एक निजी प्रतिनिधिमंडल को कब्जे वाले वेस्ट बैंक में प्रवेश करने से रोक दिया। इस दल में कनाडा की संसद के छह सदस्य (सांसद) शामिल थे। कनाडा में इस्त्राइल के दूतावास ने कहा कि इस समूह को इसलिए रोका गया क्योंकि इसके कुछ संबंध इस्लामिक रिलीफ वर्ल्डवाइड नाम की संस्था से बताए जा रहे हैं। इस्त्राइल इस संस्था को आतंकी संगठन मानता है। इस मामले पर कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद ने अपने नागरिकों, खासकर सांसदों, के साथ हुए इस बर्ताव पर आपत्ति जताई है। इतना ही नहीं कनाडा के पीएम मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी की ओंटारियो से सांसद इकरा खालिद ने सीमा पर खड़े इस्त्राइली सुरक्षाकर्मियों पर धक्का-मुक्की का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि वह भी इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस्त्राइली सीमा अधिकारियों ने उन्हें कई बार धक्का दिया। दावा- इस्त्राइली अधिकारियों ने सांसदों को दिया धक्का मामले में इकरा खालिद ने कहा कि जब वह अपने दल के एक सदस्य की मदद के लिए आगे

सीजर ने 40 मीटर दूर से आतंकियों पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर आतंकी हमले के दौरान जिस पुलिसकर्मी ने आतंकी साजिद को ढेर किया, अब उनकी बहादुरी की चर्चा की जा रही है। डिटेक्टिव सीनियर कॉन्स्टेबल सीजर बाराजा पिछले 16 साल से पुलिस सेवा में हैं। इस हमले के दौरान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सीजर आतंकियों पर गोली बरसाते दिख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले में 15 लोगों की जान चली गई। इस वारदात को रोकने में जिस पुलिस अधिकारी ने अहम भूमिका निभाई, अब उनका नाम सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमलावर को मार गिराने वाले अधिकारी डिटेक्टिव सीनियर कॉन्स्टेबल सीजर बाराजा हैं। सादे कपड़ों में ड्यूटी पर तैनात थे सीजर सीजर बाराजा पिछले 16 साल से पुलिस सेवा में हैं। वह बॉन्डी इलाके में ही तैनात हैं और सादे कपड़ों में ड्यूटी पर थे। घटना के दौरान का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह एक पेड़ के पास खड़े होकर करीब 40 मीटर दूर फुटब्रिज की ओर फायरिंग करते दिखे। इसी कार्रवाई में आतंकी साजिद अकरम मारा गया, जबकि उसका बेटा नवीद अकरम गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया है कि साजिद और नवीद ने हनुक्का कार्यक्रम के दौरान ऊंचाई से हाई-पावर हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। रियलिटी टीवी शो में कर चुके हैं काम सीजर बाराजा को उनके साथी सेस के नाम से जानते हैं। वह 2000 के दशक में एक रियलिटी टीवी शो द रिक्रूट्स में भी नजर आ चुके हैं। उस शो में उन्होंने कहा था कि वह पुलिस इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपराध से नफरत है। उन्होंने बताया था कि पुलिस बनने की ट्रेनिंग कितनी कठिन होती है और इसके लिए वह रोज कड़ी मेहनत करते थे। हालांकि, न्यू साउथ वेल्स पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि अभी जांच चल रही है और आधिकारिक तौर पर यह तय किया जा रहा है कि किस अधिकारी की गोली से आतंकी मारा गया।

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063787346044 Twitter: https://twitter.com/mantrabharat?t=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 Mobile No: 7007837917

मंत्र भारत : RNI-MPHIN/2023/88414 देवांश प्रिंटिंग प्रेस 12/12 विनय नगर सेक्टर-2 ग्वलियर(म.प्र.) से मुद्रित एंव 433 आनंन नगर डबल रोड बहोड़ा ग्वालियर से प्रकाशित एवं सम्पादित।
E-Mail : mantragwalior@gmail.com । सम्पादक : मनीष शुक्ला, मोबाइल : 7007837917 स्थानीय संपादक- आनंद त्रिवेदी । वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे का क्षेत्र ग्वालियर न्यायालय होगा।